सांध्य दैनिक
नई दृष्टिबिंदु
सच की शक्ति, जनता की दृष्टि
PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

सु-विचार

" प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है... !!
अज्ञात...

वर्ष–01 अंक–294 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, रविवार 15 नवंबर 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य –2 रुपए

शहीद गोपनीय सैनिक के परिवार को नौकरी में उम्र की बाधा, 15 लाख सहायता पर सवाल

नक्सल उन्मूलन नीति के प्रावधान 4.3.3 के तहत सहायता की मांग

नई दृष्टिबिंदु / कांकेर

उत्तर बस्तर कांकेर जिले में नक्सलियों के हाथों मारे गए गोपनीय सैनिक के परिवार को शासकीय नौकरी देने में उम्र का हवाला दिए जाने का मामला सामने आया है। इसे लेकर शासन की पुनर्वास नीति के तहत परिवार को न्याय दिलाने की मांग उठ रही है।

जानकारी के अनुसार कलेक्टर कार्यालय कांकेर द्वारा 30 अक्टूबर 2026 को पुलिस अधीक्षक कांकेर को भेजे गए पत्र में दो नक्सल पीड़ित परिवारों के मामलों का उल्लेख किया गया है। पत्र में बताया गया है कि संबंधित परिवार के सदस्य



की उम्र 45 वर्ष से अधिक होने के कारण शासकीय नौकरी के लिए पात्रता नहीं बन रही है।

इस पर सवाल उठ रहा है कि यदि उम्र के कारण नौकरी नहीं दी जा सकती तो क्या परिवार को नौकरी के एवज में निर्धारित सहायता भी नहीं मिलेगी। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति–2025 के प्रावधान 4.3.3 में स्पष्ट व्यवस्था है कि हत्या के ऐसे मामलों में, जिनमें किसी कारणवश शासकीय सेवा प्रदान नहीं की जा सकती, नक्सल पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसमें 12 लाख रुपये तीन वर्ष के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा करने और शेष 3 लाख रुपये तत्काल प्रदान करने का प्रावधान है।

मांग की जा रही है कि जिला प्रशासन नीति के प्रावधान के तहत पात्रता की जांच कर 15 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत करने की कार्रवाई करे और पीड़ित परिवार को लिखित जानकारी दे।

जनजातीय गौरव दिवस पर आज से धान खरीदी का महाअभियान शुरू

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अन्नदाता किसानों की मेहनत को सम्मान, उनकी उपज का बेहतर मूल्य और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026–27 की धान खरीदी नीति में महत्वपूर्ण किसान हितैषी प्रावधान किए हैं। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की एक समान आदान सहायता राशि देने की व्यवस्था की गई है। इससे निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचने वाले किसानों को भी उनके पात्र रकबे के अनुसार पूरी सहायता राशि का लाभ मिल सकेगा। यह व्यवस्था किसानों को अपनी वास्तविक पैदावार और आवश्यकता के अनुरूप धान विक्रय करने की सुविधा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में आगामी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेशव्यापी धान खरीदी महाअभियान प्रारंभ होने जा रहा है। राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026–27 में प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान उपार्जन की व्यवस्था की है।

शराब की लत से परेशान बहन ने भाई की सीलबट्टा से मारकर हत्या की



नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग–उतई

उतई थाना क्षेत्र के ग्राम गोड़पेण्ड्री में भाई की हत्या के मामले का पुलिस ने चंद घंटों में खुलासा कर आरोपी बहन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 14 नवंबर को थाना उतई को ग्राम गोड़पेण्ड्री में मर्ग की सूचना मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो 40 वर्षीय धर्मेन्द्र पाल का शव मिला। शव के निरीक्षण में बाईं आंख के ऊपर किसी ठोस वस्तु से प्राणघातक वार के निशान मिले।

प्रारंभ में मृतक की बहन और सूचनाकर्ता धन्नी धनकर (34) ने किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हमला कर हत्या करने की बात कही थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। घटनास्थल और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से हत्या की आशंका पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।

विवेचना में पुलिस को बहन पर संदेह हुआ। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर धन्नी धनकर ने हत्या करना स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि भाई की शराब पीने की आदत से वह परेशान थी। इसी कारण उसने घर में रखे सीलबट्टा (लोढ़ा) से भाई के सिर पर वार कर हत्या कर दी।

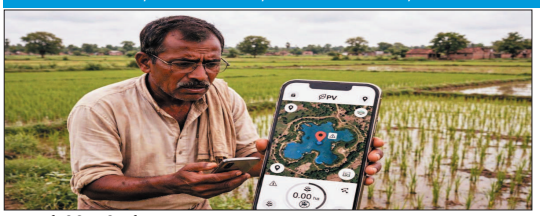
पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त सीलबट्टा जब्त कर लिया है। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उतई पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की जा रही है।

पाहंदा में युवक पर जानलेवा हमला, 3 आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग। थाना अमलेश्वर क्षेत्र के ग्राम पाहंदा में आपसी विवाद में युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 9 नवंबर की रात बाजार चौक के पास विवाद के दौरान आरोपियों ने त्रिदेव बंघे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसके पेट में गंभीर चोट आई। घायल को एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट पर थाना अमलेश्वर में अपराध क्रमांक 164/2026 धारा 109 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। अमलेश्वर थाना और साइबर क्राइम दुर्ग की संयुक्त टीम ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर सूचना पर चंगोराभाटा रायपुर से घेराबंदी कर तीनों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपी गोपी साहू (32), अंकित सोनकर (19) और भेदराज निर्मलकर (25) सभी चंगोराभाटा डीडी नगर रायपुर के निवासी हैं। उनके पास से घटना में प्रयुक्त बटनदार धारदार हथियार, 2 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल जब्त किए गए। तीनों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, जबकि 2 अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

डिजिटल सर्वे में गड़बड़ी से किसान हुए परेशान, धान बेचने पर संकट

धान बेचने पर संकट, खेत में धान लगा, रिकॉर्ड में रकबा कम, तहसीलदार बोले – सुधार का अधिकार नहीं



नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

प्रदेश में धान खरीदी शुरू होने से पहले डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसान पंजीयन में तकनीकी गड़बड़ियों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कहीं खेत में धान लगा है लेकिन रिकॉर्ड में रकबा कम दिख रहा है, तो कहीं दूसरी फसल की गलत एंट्री हो गई है। इससे किसान धान बेच पाएंगे या नहीं, इसको लेकर संशय बना हुआ है।

दरअसल कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ वर्ष 2026 के लिए पात्र किसानों को 13,839 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता देने का प्रावधान है। सहायता राशि का निर्धारण सत्यापित रकबे के आधार पर होना है। रिकॉर्ड में रकबा कम होने से किसान धान बेचने और योजना का लाभ लेने दोनों में परेशान हो सकते हैं।

छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के मुताबिक 11 नवंबर की प्रारंभिक तुलनात्मक रिपोर्ट में पिछले साल की तुलना में प्रदेश का धान रकबा करीब 2 लाख 51 हजार 799 हेक्टेयर यानी 7.61 प्रतिशत कम प्रदर्शित हो रहा है। संघ ने इसका जिला और खसरा वार परीक्षण कराने की मांग की है।

संघ का कहना है कि सर्वे, पीवीपी ऐप और एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री में सुधार और अनुमोदन से जुड़ी सुविधाएं स्थानीय राजस्व अधिकारियों की आईडी में उपलब्ध नहीं हैं। दुर्ग जिले में ही 2 हजार से अधिक किसानों के 8365 खसरा धान खरीदी पोर्टल में अपडेट नहीं हुए हैं। किसान सोसायटी में शिकायत कर रहे हैं और सोसायटी वाले तहसीलदार से, लेकिन तहसीलदारों का कहना है कि उनके पास सुधार का अधिकार ही नहीं है। इन्हीं समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर शुक्रवार को दुर्ग संभाग के तहसीलदार और नायब तहसीलदार एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।

इधर पटवारी एक माह से हड़ताल पर हैं, उन्होंने काम और आईडी पूरी तरह बंद कर दी है। इससे नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और कोर्ट केस प्रभावित हो रहे हैं। जिले में आय, जाति, निवास के करीब 33 हजार आवेदन पेंडिंग पड़े हैं, जिससे छात्र–छात्राओं को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। प्रशासन ने 138 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस दिया है और वेतन रोक दिया है, फिर भी हड़ताल जारी है।

डिजिटल सर्वे में गड़बड़ी से किसान परेशान, धान बेचने पर संकट, खेत में धान लगा, रिकॉर्ड में रकबा कम, तहसीलदार बोले - सुधार का अधिकार नहीं

प्रदेश में धान खरीदी शुरू होने से पहले डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसान पंजीयन में तकनीकी गड़बड़ियों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कहीं खेत में धान लगा है लेकिन रिकॉर्ड में रकबा कम दिख रहा है, तो कहीं दूसरी फसल की गलत एंट्री हो गई है। इससे किसान धान बेच पाएंगे या नहीं, इसको लेकर संशय बना हुआ है। दरअसल कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ वर्ष 2026 के लिए पात्र किसानों को 13,839 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता देने का प्रावधान है। सहायता राशि का निर्धारण सत्यापित रकबे के आधार पर होना है। रिकॉर्ड में रकबा कम होने से किसान धान बेचने और योजना का लाभ लेने दोनों में परेशान हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के मुताबिक 11 नवंबर की प्रारंभिक तुलनात्मक रिपोर्ट में पिछले साल की तुलना में प्रदेश का धान रकबा करीब 2 लाख 51 हजार 799 हेक्टेयर यानी 7.61 प्रतिशत कम प्रदर्शित हो रहा है। संघ ने इसका जिला और खसरा वार परीक्षण कराने की मांग की है।

दुर्ग में 8365 खसरा अपडेट नहीं : संघ का कहना है कि सर्वे, पीवीपी ऐप और एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री में सुधार और अनुमोदन से जुड़ी सुविधाएं स्थानीय राजस्व अधिकारियों की आईडी में उपलब्ध नहीं हैं। दुर्ग जिले में ही 2 हजार से अधिक किसानों के 8365 खसरा धान खरीदी पोर्टल में अपडेट नहीं हुए हैं। किसान सोसायटी में शिकायत कर रहे हैं और सोसायटी वाले तहसीलदार से, लेकिन तहसीलदारों का कहना है कि उनके पास सुधार का अधिकार ही नहीं है। **तहसीलदार एक दिन के सामूहिक अवकाश पर :** इन्हीं समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर शुक्रवार को दुर्ग संभाग के तहसीलदार और नायब तहसीलदार एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।

पटवारी हड़ताल से 33 हजार आवेदन अटके : इधर पटवारी एक माह से हड़ताल पर हैं, उन्होंने काम और आईडी पूरी तरह बंद कर दी है। इससे नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और कोर्ट केस प्रभावित हो रहे हैं। जिले में आय, जाति, निवास के करीब 33 हजार आवेदन पेंडिंग पड़े हैं, जिससे छात्र–छात्राओं को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। प्रशासन ने 138 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस दिया है और वेतन रोक दिया है, फिर भी हड़ताल जारी है।

प्रार्थी की अशिक्षा का फायदा उठाकर बैंक खाते से 2.30 लाख का गबन, आरोपी हुआ गिरफ्तार



नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

वैशाली नगर थाना पुलिस ने बैंक खाते से बिना जानकारी करीब 2 लाख 30 हजार रुपये निकालकर गबन करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार प्रार्थी दिनेश यादव निवासी राजीव नगर सुपेला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह पढ़ा–लिखा नहीं है। उसका कैनरा बैंक सुपेला में खाता है। वह बैंक लेनदेन के लिए अपने साथ काम करने वाले होरी लाल यादव की मदद लेता था। इसी कारण आरोपी को उसके खाते की पूरी जानकारी थी।

आरोपी ने इसका फायदा उठाकर 24 अगस्त 2025 से 7 मार्च 2026 के बीच अलग–अलग किस्तों में प्रार्थी के खाते से करीब 2 लाख 30 हजार रुपये निकाल लिए। शिकायत पर थाना वैशाली नगर में अपराध क्रमांक 430/2026 धारा 305 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई। बैंक स्टेटमेंट और गवाहों के कथन के आधार पर आरोपी से पूछताछ की गई, जिसमें उसने राशि निकालकर खर्च करना स्वीकार किया।

पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी होरी लाल यादव उम्र 30 वर्ष निवासी साई इंद्रा नगर ठेकरापारा वार्ड 16 थाना सुपेला को 13 नवंबर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि बैंक खाता, एटीएम, पासबुक और बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी किसी अन्य के साथ साझा न करें।

सैलरी की पटरी पर ठेकेदार का कब्जा, सफाईकर्मियों के हक पर डाका

रायपुर। यात्रियों को चमकते कोच और स्वच्छ सफर मुहैया कराने वाले रेल सफाईकर्मियों की जिंदगी आर्थिक शोषण के अंधेरे में फंसी है। रायपुर रेल मंडल में ट्रेनों के भीतर साफ–सफाई का जिम्मा संभाल रही ठेका कंपनी 'किंग एक्सपर्ट्स इन सिक्योरिटी सॉल्यूशन' पर कर्मचारियों की मेहनत की कमाई हड़पने के गंभीर आरोप लगे हैं। दस्तावेजों और पीड़ित कर्मचारियों के बयानों से जो परतें खुल रही हैं, वह श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाने वाली हैं। मामला केवल वेतन कटौती तक सीमित नहीं है, बल्कि कर्मचारियों के बैंक खाते और एटीएम कार्ड तक ठेकेदार के कब्जे में होने की बात सामने आई है। नियम के अनुसार सफाईकर्मियों का मासिक वेतन 18 से 20 हजार रुपये के बीच निर्धारित है। लेकिन पीड़ित कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 3–4 साल से जब से इस कंपनी ने ठेका संभाला है, उनके हाथ में हर महीने महज 10 हजार रुपये ही आ रहा है। हर महीने सीधे 8 हजार रुपये की कटौती की जा रही है।

पारदर्शिता के लिए वेतन सीधे कर्मचारियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। आरोप है कि कंपनी के प्रतिनिधि ने कर्मचारियों के एटीएम कार्ड अपने पास रख लिए हैं। खाते में पूरी तनख्वाह आते ही अतिरिक्त राशि एटीएम से निकाल ली जाती है और कर्मचारियों को केवल 10 हजार रुपये थमा दिए जाते हैं। पीड़ितों का कहना है कि न उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है, न ही अवकाश और मेडिकल सुविधा मिलती है। शिकायत करने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है।

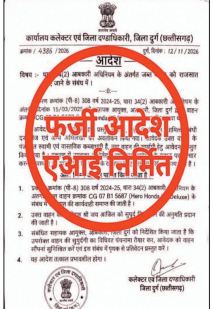
एआई से बनाया कलेक्टर का फर्जी आदेश, आबकारी से जप्त बाइक छुड़ाने पहुंचे दो आरोपी गिरफ्तार

भिलाई भट्ठी पुलिस ने किया खुलासा, मोबाइल और फर्जी आदेश जप्त

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

कलेक्टर दुर्ग का फर्जी आदेश तैयार कर आबकारी कार्यालय से जप्त मोटरसाइकिल छुड़ाने की कोशिश करने वाले दो आरोपियों को भिलाई भट्ठी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 14 नवंबर को जय कुमार आडिल उर्फ पप्पू (32) और युगल किशोर शर्मा उर्फ राजा (40), दोनों निवासी ग्राम मोहरेंगा थाना नंदिनी नगर, आबकारी नियंत्रण कक्ष सेक्टर–01 भिलाई पहुंचे थे। उन्होंने वर्ष 2025 के आबकारी प्रकरण में जप्त मोटरसाइकिल क्रमांक CG 07 B 15687 होंडा HF डिलक्स को सुपुर्दनामा पर लेने के लिए कलेक्टर दुर्ग के नाम से जारी आदेश प्रस्तुत किया।

सत्यापन में आदेश फर्जी और कूटरचित पाया गया। रिपोर्ट पर थाना भिलाई भट्ठी में



अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। पूछताछ में दोनों ने अककी मदद से फर्जी शासकीय आदेश बनाना स्वीकार किया।

पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन और फर्जी आदेश की प्रति जप्त की है। दोनों आरोपियों को 14 नवंबर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि अकया डिजिटल माध्यमों से फर्जी शासकीय दस्तावेज तैयार करना और उपयोग करना दंडनीय अपराध है।

शराब घोटाला : चैतन्य बघेल की 355 प्लॉट वाली कॉलोनी ईडी के कब्जे में



भिलाई। छत्तीसगढ़ के 2,883 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के दुर्ग जिले के जामगिरी स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट 'विडूल ग्रीन्स' के 355 प्लॉट ईडी ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। रायपुर जोनल कार्यालय के अधिकारी शनिवार दोपहर करीब 3 बजे जामगिरी स्थित प्रोजेक्ट पहुंचे। वहां संपत्ति को कब्जे में लेने की प्रक्रिया पूरी कर सूचना पट्ट लगाया और आदेश चस्पा किया। इसके साथ ही चैतन्य के भिलाई–3 स्थित निवास '1/7 मानसरोवर आवासीय परिसर' की बाहरी दीवार पर भी कब्जे का आदेश लगाया गया। **26.43 करोड़ की संपत्ति, 355 प्लॉट पर कब्जा :** कॉलोनी में कुल 385 प्लॉट हैं। इनमें पहले बिक चुके 30 प्लॉट को कार्रवाई से अलग रखा गया है। 355 प्लॉट में एक व्यावसायिक प्लॉट भी शामिल है। इस संपत्ति की कीमत 26.43 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसमें जमीन की कीमत 9.49 करोड़ और विकास कार्यों की लागत 16.95 करोड़ रुपये बताई गई है। ईडी का दावा है कि चैतन्य ने अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म 'बघेल डेवलपर्स' के माध्यम से यह प्रोजेक्ट विकसित किया था और शराब घोटाले से अर्जित 18.90 करोड़ रुपये इसमें निवेश किए गए। यह कार्रवाई दिल्ली में पीएमएलए के निर्णायक प्राधिकरण द्वारा संपत्ति की कुर्की की पुष्टि के बाद की गई है। इससे पहले नवंबर 2025 में ईडी ने इस प्रोजेक्ट समेत चैतन्य की कुल 61.20 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की थीं। **क्या है कब्जे का कानूनी मतलब :** पीएमएलए के तहत संपत्ति का कब्जा लेने का अर्थ है कि ट्रायल के दौरान कुर्की प्रभावी रहेगी और इसे खरीदा–बेचा नहीं जा सकेगा। इससे स्वामित्व सरकार को हस्तांतरित नहीं होता, दोषसिद्धि होने पर संपत्ति स्थायी रूप से जब्त की जाती है। **ईडी का आरोप :** एजेंसी का आरोप है कि तत्कालीन सीएम के बेटे होने के कारण चैतन्य का सिंडिकेट पर सीधा प्रभाव था और वे अवैध कमाई का हिसाब रखते थे। रकम जुटाने, निवेश और बांटने के बड़े फैसले उनके निर्देश पर लिए जाते थे। ईडी ने जुलाई 2025 में चैतन्य को गिरफ्तार किया था। हालांकि पूर्व सीएम भूपेश बघेल इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं।



भूपेश बघेल का बैलगाड़ी से ऐतिहासिक स्वागत, राउत नाचा की पारंपरिक वेशभूषा ने केंद्रित किया आकर्षण

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर बैलगाड़ी से आमजनों को अभिवादन करते नजर आए

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

ग्राम भेड़सर में आयोजित दीपावली महोत्सव एवं भव्य रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोकसंस्कृति, परंपरा और ग्रामीण जनजीवन का संगम देखने को मिला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का क्षेत्रवासियों ने छत्तीसगढ़ी परंपरा के अनुरूप बैलगाड़ी से ऐतिहासिक एवं भव्य स्वागत किया। बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामीणों ने उत्साह, उमंग और आत्मीयता के साथ उनका अभिनंदन किया।

बैलगाड़ी में सवार होकर भूपेश बघेल ने उपस्थित जनसमुदाय का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष राकेश ठाकुर एवं विशिष्ट अतिथि पीसीसी संयुक्त महामंत्री राजेन्द्र साहू तथा महापौर निर्मल कोसरे भी उनके साथ बैलगाड़ी में सवार नजर आए। पारंपरिक बैलगाड़ी से किया गया यह स्वागत ग्रामीण संस्कृति, कृषि परंपरा और छत्तीसगढ़ की अस्मिता का जीवंत प्रतीक बना। मंच पर पहुंचते ही भूपेश बघेल पारंपरिक राउत नाचा की वेशभूषा में दिखाई दिए। उनकी इस पारंपरिक छवि ने उपस्थित जनसमुदाय के बीच विशेष आकर्षण पैदा किया। लोककलाकारों की प्रस्तुतियों, पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक रंगों ने पूरे आयोजन को यादगार बना दिया।



कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की असली पहचान यहां की लोकसंस्कृति, तीज-त्योहार, किसान, मजदूर और मेहनतकश जनता है। हमारी परंपराएं केवल उत्सव मनाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक एकता, भाईचारे, आपसी सहयोग और सामूहिक खुशियों का संदेश देती हैं। बैलगाड़ी, गाड़ा-बैला, राउत नाचा और लोकपरंपराएं हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी हुई हैं। इन्हें सहेजना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि गांव और किसान छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद हैं। किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं और गरीब परिवारों के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। प्रदेश की खुशहाली का रास्ता गांवों के विकास, कृषि की मजबूती और आम जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव से होकर गुजरता है। सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारा छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत है, जिसे हर परिस्थिति में बनाए रखना आवश्यक है।

वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर अपनी बात रखते हुए श्री बघेल ने संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिकों के मताधिकार की सुरक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया और जनता के विश्वास पर निर्भर करती है। प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी के नेतृत्व में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जनभागीदारी को

खास खबर

नेहरू जयंती पर सेवादल व युवा कांग्रेस ने मरीजों को बांटे फल, वोरा और वर्मा पहुंचे जिला अस्पताल



नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

देश के प्रथम प्रधानमंत्री एवं आधुनिक भारत के निमार्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती एवं बाल दिवस के अवसर पर जिला कांग्रेस सेवादल एवं युवा कांग्रेस द्वारा दुर्ग जिला अस्पताल में फल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान चाचा नेहरू को याद करते हुए उनके विचारों और राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को नमन किया गया। कार्यक्रम में दुर्ग शहर के पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण वोरा एवं आर.एन. वर्मा विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और फल वितरित कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

इस अवसर पर अरुण वोरा ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के शिल्पकार थे। उन्होंने देश में औद्योगिक विकास, बड़े बांधों, उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बच्चों के प्रति उनके विशेष स्नेह के कारण ही उनकी जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि नेहरू जी के विचारों को याद करते हुए जरूरतमंदों की सेवा करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस सेवादल एवं युवा कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

त्योहारी सीजन में बाजारों में जाम से राहत के लिए यातायात पुलिस का अभियान तेज, नो-पार्किंग में खड़े वाहनों पर कार्रवाई

दुर्ग। त्योहारी सीजन में बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस दुर्ग ने नो-पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। पुलिस उप महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा दुर्ग-भिलाई के प्रमुख बाजारों और व्यस्त मार्गों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग में स्टेशन रोड, इंदिरा मार्केट, सराफा मार्केट और समृद्धि मार्केट तथा भिलाई में नेहरू नगर से सूर्या मॉल रोड, सुपेला संडे मार्केट, पावर हाउस मार्केट और सिविक सेंटर मार्केट में पेट्रोलिंग कर कार्रवाई की जा रही है।

अभियान के दौरान नो-पार्किंग में खड़े दोपहिया वाहनों को क्रेन से उठाकर यातायात कार्यालय भेजा जा रहा है, जबकि चारपहिया वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ई-चालान की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही दुकानदारों को सड़क पर सामान न रखने की समझाइश भी दी जा रही है। यातायात पुलिस ने बताया कि कार्रवाई का उद्देश्य केवल चालान करना नहीं, बल्कि बाजारों में लगने वाले जाम से आम नागरिकों को राहत दिलाना और पैदल राहगीरों के लिए सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना है।



ग्राम आलबरस को विकास कार्यों की सौगात, विधायक ललित चंद्राकर ने किया भूमिपूजन और लोकार्पण

गांव, गरीब, किसान, मजदूर, माताओं-बहनों और युवाओं का सर्वांगीण विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता : ललित चंद्राकर



नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ग्राम आलबरस में विकास कार्यों को गति देते हुए विधायक ललित चंद्राकर ने ग्रामीणों को 36.60 लाख रुपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। ग्राम पंचायत परिसर में आयोजित भूमिपूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने भारत माता एवं छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा-अर्चना कर विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया।

इन विकास कार्यों में कुर्मी भवन में शेड निर्माण के लिए 8 लाख रुपये, सीसी रोड निर्माण के लिए 13.60 लाख रुपये, ओपन जिम निर्माण के लिए 6 लाख रुपये तथा डोम शेड निर्माण के लिए 9 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। कुल 36.60 लाख रुपये की लागत से होने वाले इन कार्यों से गांव में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होगा तथा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सामुदायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

इस अवसर पर विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि गांवों की खुशहाली, किसानों की समृद्धि और प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना राज्य सरकार का प्रमुख संकल्प है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, माताओं-बहनों और युवाओं का सर्वांगीण विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार भी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए निरंतर प्रयासरत है। किसी भी क्षेत्र का वास्तविक विकास तभी संभव है, जब गांव मजबूत हों, किसानों को बेहतर संसाधन मिलें, युवाओं को शिक्षा एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध हों और आम नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं मिलें।

विधायक चंद्राकर ने किसानों के हित में जानकारी देते हुए बताया कि कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए किसानों को धान की निर्धारित पूरी मात्रा का विक्रय करना अनिवार्य नहीं होगा। निर्धारित मात्रा से कम धान बेचने वाले किसानों को भी सत्यापित रकबे के आधार पर पात्रतानुसार सहायता राशि का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला हैं। उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना और कृषि क्षेत्र में समृद्धि लाना सरकार की प्राथमिकता है।

विधायक ने बताया कि प्रदेश में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होगी। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन्हें मिलाकर लगभग 3100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य अन्नदाताओं के जीवन में खुशहाली लाना है। धान खरीदी की पूरी तैयारी के साथ किसानों से धान का एक-एक दाना खरीदने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। विकास कार्यों के कार्यक्रम के बाद विधायक ललित चंद्राकर ने धान खरीदी केंद्र पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने आगामी धान खरीदी की तैयारियों की जानकारी ली तथा समिति प्रबंधक और सोसायटी अध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने खरीदी केंद्र में किसानों की सुविधा, व्यवस्थाओं और तैयारियों को लेकर विशेष ध्यान देने की बात कही।

विधायक ने कहा कि मोदी की गारंटी के तहत किए गए वादों को सरकार पूरा कर रही है। 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी, महतारी वंदन योजना के तहत प्रतिमाह 1000 रुपये तथा कृषक उन्नति योजना के तहत 13,839 रुपये प्रति एकड़ तक की आदान सहायता इसके प्रमाण हैं। डबल इंजन की सरकार गांव, गरीब, किसान और महिलाओं के जीवन में खुशहाली लाने के लिए लगातार काम कर रही है। कार्यक्रम में अंडा-निकुम मंडल अध्यक्ष लिकेश्वर देशमुख, ग्राम आलबरस के सरपंच सैनिक भुवनलाल देशमुख, मंडल महामंत्री पुराण देशमुख एवं गब्बर साहू, जनपद सभापति लोमस चंद्राकर, सोसायटी अध्यक्ष ओमप्रकाश यादव, बूथ अध्यक्ष अशोक हरमुख, परस साहू, पंचगण एमंत देशमुख, श्रीमती रेणुका देशमुख, मुकुंद देशमुख, दिलीप चंदेल, दुर्गेश्वरी देशमुख, श्रीमती श्वेता हरमुख, अलखराम यादव, सोमनाथ देशमुख, योगेश्वर प्रसाद देशमुख, श्रीमती रमसिला निषाद, पुरानीक लाल चेलक, संतोष कुमार सोनवानी, सचिव श्रीमती सरस्वती टंडन सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

महापौर अलका बाघमार व सभापति ने दुकानदारों को वितरित किए 300 जोड़ी डस्टबिन



नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने और व्यापारियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से महापौर अलका बाघमार एवं सभापति श्याम शर्मा ने इंदिरा मार्केट क्षेत्र में दुकानदारों को 300 जोड़ी डस्टबिन वितरित किए। इस दौरान महापौर एवं जनप्रतिनिधियों ने फूल लाइन से प्रिया श्रृंगार सदन, सदर बाजार, मान होटल लाइन से होते हुए हटरी बाजार तक दुकानों में पहुंचकर व्यापारियों को डस्टबिन प्रदान किए और दुकान से निकलने वाले कचरे का उचित प्रबंधन करने की समझाइश दी।

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग प्रभारी नीलेश अग्रवाल, एमआईसी सदस्य ज्ञानेश्वर ताम्रकर, मनीष साहू, शशि साहू, रंजीता पाटिल,जितेंद्र महोबिया, मनीष कोठारी, स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, कुणाल सहित निगम का अमला मौजूद रहा।

महापौर अलका बाघमार ने दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यापारी अपनी दुकान से निकलने वाले कचरे को निर्धारित डस्टबिन में ही एकत्रित करें तथा निगम के कचरा संग्रहण वाहन को ही सौंपें। सड़क, नाली एवं सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने से गंदगी फैलती है, जिससे आम नागरिकों को परेशानी होती है। शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखना केवल निगम की नहीं, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। निगम प्रशासन स्वच्छता के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, ऐसे में व्यापारियों एवं नागरिकों का सहयोग बेहद जरूरी है।

डस्टबिन वितरण के दौरान कुछ दुकानों के बाहर नालियों में कचरा पड़ा देखकर महापौर ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को नाली में कचरा फेंकने वाले दुकानदारों के विरुद्ध निगम के नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही दुकानदारों को स्पष्ट हिदायत दी कि दुकान के बाहर सड़क तक सामान फैलाकर व्यवसाय न करें, जिससे आवागमन बाधित न हो और बाजार में व्यवस्था बनी रहे।महापौर ने कहा कि स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों पर निगम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सभी व्यापारी अपनी जिम्मेदारी समझें और स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाकर दुर्ग शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं व्यवस्थित बनाने में सहयोग करें।

पौधों में जीवन की उम्मीद और यादों में हरियाली संजो रहे रोम शंकर यादव, मुख्यमंत्री ने विष्णु की पाती से की सराहना

दुर्ग। प्रकृति के प्रति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प जब जीवन का उद्देश्य बन जाए, तो छोटी-सी पहल भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकती है। कुछ ऐसी ही प्रेरणादायी सोच के साथ ग्राम डूंडेरा निवासी रोम शंकर यादव अपनी संस्था हितवा संगवारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में निरंतर सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उनके लिए पौधारोपण केवल एक गतिविधि नहीं, बल्कि खुशियों को यादगार बनाने और अपनों की स्मृतियों को प्रकृति में जीवित रखने का एक भावनात्मक माध्यम है। रोम शंकर यादव और उनकी पूरी टीम ने पर्यावरण संरक्षण को सामाजिक सरोकार से जोड़ते हुए एक अनूठी पहल की है। संस्था द्वारा बच्चों के जन्मदिन, किसी प्रियजन के निधन, पुण्यतिथि तथा महापुरुषों की जयंती जैसे विशेष अवसरों पर पौधारोपण कराया जाता है।

कांग्रेस अध्यक्ष बाकलीवाल के पिता के निधन पर राहुल ने व्यक्त की शोक संवेदना

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

दुर्ग शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल के पिता सीताराम बाकलीवाल का 7 नवंबर को निधन हो गया। उनके निधन से कांग्रेस परिवार सहित राजनीतिक, सामाजिक एवं विभिन्न क्षेत्रों में शोक की लहर है।

स्वर्गीय सीताराम बाकलीवाल एक प्रतिष्ठित समाजसेवी एवं सरल, सहज व्यक्तित्व के धनी थे। वे लंबे समय से सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहे और समाजहित एवं जनसेवा के कार्यों में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते रहे। उनके निधन से परिवारजनों के साथ-साथ उनके परिचितों, शुभचिंतकों एवं सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों में भी गहरा दुःख है। श्री सीताराम बाकलीवाल के निधन की सूचना मिलने पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पत्र एवं दूरभाष के माध्यम से धीरज बाकलीवाल से चर्चा कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। राहुल गांधी ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और इस कठिन समय में परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की।

इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ,पूर्व सांसद सरोज पांडेय, झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर, सांसद विजय बघेल,शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव , पूर्व विधायक अरुण वोरा, विधायक ललित चंद्राकर, महापौर अलका बाघमार , राजेंद्र साहू सहित दुर्ग जिले के कांग्रेस एवं भाजपा नेताओं, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकताओं , पत्रकारो एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने भी सीताराम बाकलीवाल के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दुर्ग शहर कांग्रेस परिवार एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने भी शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। सभी ने स्वर्गीय सीताराम बाकलीवाल के सामाजिक योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि समाज के प्रति उनकी सेवाओं को सदैव याद किया जाएगा।

स्वर्गीय श्री सीताराम बाकलीवाल की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन 19 नवंबर को ऋषभ देव परिसर, चंडी मंदिर के पास दुर्ग में रखा गया है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा। इस अवसर पर परिवारजनों, मित्रों, कांग्रेस कार्यकताओं, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों सहित सभी शुभचिंतकों से उपस्थित होकर स्वर्गीय सीताराम बाकलीवाल को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया गया है।



मनाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती



नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के निमार्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम पंडित नेहरू के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेसजनों ने नेहरू जी के व्यक्तित्व, उनके विचारों और आधुनिक भारत के निर्माण में दिए गए उनके अतुलनीय योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि नेहरू जी का सपना था – शिक्षित, वैज्ञानिक सोच वाला और मजबूत भारत, जिसे हम सबको मिलकर साकार करना है।

इसके पश्चात मोचीपारा स्थित आंगनवाड़ी (बाल मंदिर) में बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ बच्चों को फल, बिस्किट एवं मिठाई वितरित की गई। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान देखकर पूरा वातावरण खुशियों से भर गया। कांग्रेसजनों ने बच्चों के साथ समय बिताया, उन्हें नेहरू जी के जीवन के बारे में बताया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग के अध्यक्ष अलताफ अहमद ने कहा कि पंडित नेहरू जी बच्चों को बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उनकी जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों का भविष्य ही देश का भविष्य है। हमारा कर्तव्य है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा संस्कार मिले।

कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रायसिंह धिकोला, अजय मिश्रा, राहुल शर्मा, सुमित घोष, पूर्व एल्डरमैन देव सिन्हा, कल्याण सिंह ठाकुर, अली असगर, रवि कोसरिया, पाशी अली, हिमांशु शर्मा उपस्थित थे।

शहीदों का बलिदान राष्ट्र की अमूल्य धरोहर, उनके परिवारों का सम्मान हम सभी का दायित्व : राज्यपाल

शौर्य दिवस समारोह में राज्यपाल ने शहीद परिवारों का किया सम्मान, वीर जवानों के त्याग और समर्पण को किया नमन

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर-रायगढ़



राज्यपाल रमेन डेका कल रायगढ़ के शासकीय पॉलिटेक्निक ऑडिटोरियम में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयोजित शौर्य दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों का सम्मान किया और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए दिए गए उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि देश की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए वीर जवानों का त्याग और समर्पण सदैव स्मरणीय रहेगा।

एक सैनिक का बलिदान केवल उसका व्यक्तिगत बलिदान नहीं होता, बल्कि उसका पूरा परिवार भी राष्ट्र के लिए त्याग करता है। शहीदों के परिवारों का सम्मान करना केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी और कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि शहीद परिवारों के प्रति सम्मान और सहयोग किसी एक आयोजन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनके सुख-दुख में सहभागी बनना हम सभी का दायित्व है।

राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के विरुद्ध सुरक्षा बलों के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतियों के बीच जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया है। अनेक जवानों ने देश और प्रदेश की शांति एवं सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने युवाओं से शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेते हुए उनके साहस, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र के प्रति समर्पण को आत्मसात करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देशभक्ति केवल नारों तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना और राष्ट्र के विकास में योगदान देना भी सच्ची देशभक्ति है। उन्होंने सभी से शहीदों के त्याग और बलिदान को सदैव स्मरण रखने तथा सशक्त, समृद्ध, सुरक्षित एवं विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लेने की अपील की। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, ब्रिगेडियर आर शंकर, कमाण्डेड अजय सिंह बिसेन सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने भारतीय सेना में जाने के इच्छुक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की। इनमें सैनिक स्कूल में अध्ययनरत अंकित पटेल, तोयम पटेल, स्तव्य साहू, जयेश सिदार एवं सृष्टि राठिया तथा कक्षा 9वीं के नवनीत मेहर, भुवनेश पटेल एवं अर्नव गुप्ता शामिल थे। इसी प्रकार ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई की कलाडी श्रीनिधि एवं भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के आर.बालाजी को प्रोत्साहन राशि दी गई।

खास खबर

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्ट्रीट वेंडर की चाय का लिया लुत्फ, पथ विक्रेताओं के साथ किया लंच



नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित स्वनिधि महोत्सव में स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा लगाए गए फूड स्टॉल्स के भ्रमण के दौरान उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने स्ट्रीट वेंडर के हाथों की चाय का लुत्फ लिया। उनके साथ स्टॉल देख रहे जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मिट्टी के कुल्हड़ में चाय की चुस्कियां लीं। श्री साव ने फूड-स्टॉल्स के अवलोकन के दौरान पथ विक्रेताओं से बात कर उनके व्यवसाय की जानकारी ली और पीएम स्वनिधि योजना का फीडबैक लिया। उन्होंने कार्यक्रम के बाद महिला पथ विक्रेताओं के साथ बैठकर लंच किया।

स्वनिधि महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के दो लाभार्थियों ने उप मुख्यमंत्री श्री साव से अपनी कहानी साझा की। धमतरी के दिलीप यादव ने बताया कि उन्होंने 10 हजार रुपए के ऋण से कारोबार शुरू किया था। उन्होंने समय पर ऋण की किस्तें भरकर अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए दूसरे चरण में 20 हजार रुपए और तीसरे चरण में 50 हजार रुपए का भी ऋण लिया। दिलीप ने बताया कि वे ठेले पर प्लास्टिक के सामान बेचते हैं। पीएम स्वनिधि से मिले ऋण से उनका कारोबार आगे बढ़ा और परिवार की स्थिति में भी सुधार आया।

फिंगेश्वर की श्रीमती सुशीला श्रीवास्तव ने भी उप मुख्यमंत्री श्री साव से अपने अनुभव साझा की। उन्होंने बताया कि वे सिलाई का काम करती हैं। पहले चरण में मिले 10 हजार रुपए के ऋण की किस्त पटाने के बाद अपने काम को बढ़ाने के लिए उन्होंने दूसरे चरण में 20 हजार रुपए और तीसरे चरण में 50 हजार रुपए का ऋण लिया है। पीएम स्वनिधि योजना से उसके काम और परिवार के हालात में काफी बदलाव आया है। अब वे और उनका परिवार बेहतर तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं।



अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के कल्याण से बनेगा विकसित भारत : अरुण साव

उप मुख्यमंत्री ने पथ विक्रेताओं से किया संवाद, नगरीय प्रशासन विभाग और सूडा द्वारा स्वनिधि महोत्सव का आयोजन

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर



उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव आज राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित स्वनिधि महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने महोत्सव में पथ विक्रेताओं से सीधे संवाद कर उनके व्यवसाय, परिवार और पीएम स्वनिधि योजना से उनके कार्यों व जीवन में आए बदलावों की जानकारी ली। उन्होंने लाभार्थियों को चेक, यूपीआई पेमेंट बॉक्स तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने ऑडिटोरियम परिसर में स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा लगाए गए फूड स्टॉल का भी अवलोकन किया। सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, विधायक मोतीलाल साहू और पुरंदर मिश्रा, रायपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे और सभापति सूर्यकांत राठौर भी महोत्सव में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बैंकों, उनकी शाखाओं और नगरीय निकायों को सम्मानित किया। महोत्सव में पथ विक्रेताओं को वित्तीय साक्षरता और डिजिटल भुगतान की भी जानकारी दी गई। इस दौरान प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंतर्गत 'उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम' की थीम पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया था।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम में पथ विक्रेताओं से संवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेहनतकश लोगों की परेशानियों को समझकर पीएम स्वनिधि योजना शुरू की है। इस योजना ने छोटे कारोबारियों को साहूकारों पर निर्भरता से बाहर निकालकर बैंकों से जोड़ने और अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने का अवसर दिया है। समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के कल्याण से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं में उसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की सोच और संवेदना झलकती है। कोरोना के भयावह दौर में जब सड़कें सूनी थीं, काम-धंधे बंद हो गए थे और बड़ी संख्या में लोगों के सामने रोजगार तथा परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क किनारे छोटे-मोटे कारोबार करने वालों की चिंता की। उन्होंने जून-2020 में पीएम स्वनिधि योजना शुरू की, ताकि ऐसे लोगों को दोबारा अपना कारोबार खड़ा करने के लिए आर्थिक सहारा मिल सके।

श्री साव ने पथ विक्रेताओं से कहा कि वे अपने काम को कभी छोटा न समझें। रेहड़ी, ठेले और सड़क किनारे दुकान लगाकर आजीविका चलाने वाले लोग शहर और प्रदेश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी मेहनत से न केवल उनके परिवार चलते हैं, बल्कि शहरों की रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी होती हैं। उन्होंने लाभार्थियों से अपने कारोबार को लगातार आगे बढ़ाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक लाभार्थी का लक्ष्य योजना के तीसरे चरण तक पहुंचकर 50 हजार रुपए का ऋण प्राप्त करना और अपने व्यवसाय का विस्तार करना होना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले पीएम स्वनिधि महोत्सव में ऑडिटोरियम ऐसे कारोबारियों से भरा होगा, जिन्होंने तीसरे चरण का ऋण प्राप्त कर लिया होगा और जिनके पास यूपीआई क्रेडिट कार्ड भी होगा।

सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ने कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि पीएम स्वनिधि योजना में जरूरतमंदों को बिना गारंटर के ऋण मिलता है। समय पर ऋण की किस्त पटाने वालों को सात प्रतिशत का ब्याज अनुदान भी मिलता है। यह योजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने बताया कि रायपुर नगर निगम में वर्ष 2030 तक 53 हजार स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक शहर के 33 हजार से अधिक पथ विक्रेताओं को योजना का लाभ दिया गया है। उन्होंने महिला उद्यमियों से अपील की कि वे पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लेकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं और आर्थिक रुप से सशक्त बनें।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने महोत्सव में पीएम स्वनिधि योजना के उद्देश्यों और प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में एक लाख 23 हजार से अधिक पथ विक्रेता योजना का लाभ लेकर आत्मनिर्भरता के साथ राज्य और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। राज्य में इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हम सभी कृत संकल्पित हैं। उन्होंने नगरीय निकायों और बैंकों से कहा कि वे संवेदनशीलता के साथ ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स तक योजना का लाभ पहुंचाएं। उन्हें वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करें। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक नीलेशकुमार क्षीरसागर, सूडा के सीईओ सुमीत अग्रवाल और रायपुर नगर निगम के आयुक्त संबित मिश्रा सहित पार्षदगण, रायपुर संभाग के विभिन्न नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि, अधिकारी, बैंकों के प्रतिनिधि एवं पीएम स्वनिधि के लाभार्थी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने की शिष्टाचार भेंट



राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह तथा देश के अन्य प्रदेशों के राज्य निर्वाचन आयुक्तों ने 11 नवम्बर 2026 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में सौजन्य भेंट की। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह द्वारा प्रदेश के बस्तर संभाग में पिछले वर्ष सम्पन्न हुए स्थानीय निकायों के शांतिपूर्ण चुनावों में आई चुनौतियों व आयोग द्वारा अपनाई गई रणनीति से संबंधित एक बुकलेट की प्रति भी राष्ट्रपति कार्यालय को भेंट की गई।

सम्मान समारोह शासन की योजनाओं को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने में आंगनबाड़ी कर्मियों की भूमिका अहम

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं छग के उज्ज्वल भविष्य की शिल्पकार: मंत्री लक्ष्मी

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

आंगनबाड़ी केवल एक केंद्र नहीं, बल्कि बच्चे के जीवन की पहली पाठशाला है। कार्यकर्ता और सहायिकाएं बच्चों के सुरक्षित, स्वस्थ और सुपोषित भविष्य की नींव रखती हैं। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने यह बात सिविल लाइन्स स्थित सर्किट हाउस में आयोजित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका सम्मान समारोह में कही।

महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला रायपुर के तत्वावधान में आयोजित समारोह में जमीनी स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकताओं और सहायिकाओं को मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों ने सम्मानित किया। इस अवसर पर पोषित बचपन, समृद्ध छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को साकार करने में आंगनबाड़ी कर्मियों के योगदान की सराहना की गई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने बाल विवाह रोकने की शपथ भी ली।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं गर्भवती माताओं की देखभाल से लेकर बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण और प्रारंभिक शिक्षा तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाती हैं।



वे गांव-गांव और घर-घर तक शासन की योजनाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती हैं। दूरस्थ गांवों और कठिन परिस्थितियों में भी उनके सेवाभाव तथा समर्पण से बच्चों और माताओं को जरूरी सेवाएं मिलती हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों का सुरक्षित, स्वस्थ और



खुशहाल भविष्य बनाना सामूहिक जिम्मेदारी है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में महिलाओं, बच्चों और पोषण के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। महतारी वंदन योजना, कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान और हर घर मुनगा जैसी पहलों के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा संकल्प है कि कोई भी बच्चा कुपोषण का शिकार न हो और हर गर्भवती माता को उचित पोषण एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। मंत्री ने सम्मानित कार्यकताओं और सहायिकाओं को बधाई देते हुए कहा कि यह समारोह उनके परिश्रम, त्याग और सेवाभाव के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने सभी से बच्चों और माताओं के बेहतर भविष्य के लिए इसी ऊर्जा और समर्पण के साथ कार्य करते रहने का आग्रह किया। समारोह में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष संदीप यदु, महिला एवं बाल विकास विभाग की सभापति श्रीमती शैल महेंद्र साहू तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री शैल ठाकुर सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं शामिल हुईं।

संपादकीय

साय सरकार ने साबित किया हम हैं किसान हितैषी

छत्तीसगढ़ की राजनीति में किसान एक बड़ा वोट बैंक है उसे जो प्रभावित कर पाता है, वह सत्ता पर रहता है और आगे भी उसके सत्ता में रहने की संभावना बनी रहती है, इसलिए कोई भी सरकार हो वह सत्ता में है तो जब भी उसे मौका मिलता है तो यह साबित करने से नहीं चूकती है कि वह किसान हितैषी है और उसने किसानों के हित में निरंतर फैसले किए है। जब भी जरूरत पड़ी किसानों के हित में फैसला लेने की तो सत्तारूढ़ सरकार ने फैसला लिया है। राज्य में किसान हित में बहुत सारे फैसले हो चुके हैं,जैसे प्रति क्विंटल किसानों से ज्यादा धान खरीदना,प्रति क्विंटल या प्रति एकड़ किसानों को सबसे ज्यादा पैसा देना, धान के बोनस व समर्थन मूल्य का पैसा एकमुश्त किसानों के खाते में आन लाइन भेजना।सोसायटी में टोकन कटाने किसानों को असुविधा न हो इसके लिए आनलाइन टोकन की सुविधा।हर साल किसानों का ज्यादा से ज्यादा धान खरीदना इन सारे फैसलों से सरकार ने किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने का प्रयास किया है और उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया है।

इस साल अक्टूबर में अर्नब तूफान के चलते राज्य के कई इलाकों में धान की फसल को नुकसान पहुंचा है।राज्य के कई इलाकों के किसानों को राहत की जरूरत भी है।ऐसे में सरकार ने यह फैसला करके कि किसान को प्रति एकड़ 13839 रुपए बोनस दिया जाएगा चाहे धान उसके एक एकड़ में 21 क्विंटल हुआ हो या न हुआ है।साय सरकार का यह फैसला किसान हित में लिया गया ऐसा फैसला है जिससे राज्य के किसानों की नुकसान की भरपाई तो होगी ही,पांच एकड़ वाले किसानों को आर्थिक रूप में मजबूती भी मिलेगी।यानी साय सरकार का यह फैसला एक तरह से कहा जा सकता है कि किसानों के सशक्तीकरण का सराहनीय फैसला है।धान खरीदी राज्य में 15 नवंबर से होगी। उसके पहले यह फैसला लिए जाने से राज्य के 27 .50 लाख किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।पहले की नीति के मुताबिक किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने पर ही बोनस मिला करता था,इस बार किसानों को नुकसान हुआ इसलिए साय सरकार ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।

साय सरकार ने खरीफ वर्ष 26-27 के लिए 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का समर्थन मूल्य तय किया है। इसमें केंद्र सरकार का एमएसपी 2441 रुपए प्रति क्विंटल है, अंतर की राशि 659 रुपए बोनस है, जो राज्य सरकार देगी। राज्य सरकार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदती रही है। तूफान के कारण राज्य के कई इलाकों के किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है,इसी के साथ बस्तर व सरगुजा संभाग के किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान पैदा नहीं कर पाते हैं। इससे उनको कम पैसा मिलता था। साय सरकार के फैसले से तूफान से नुकसान की भरपाई हो होगी ही, उन किसानों को भी खूब फायदा होगा जिसने खेत में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान नहीं होता है,क्योंकि उनको धान कितना भी हो बोनस तो प्रति एकड़ 21 क्विंटल के हिसाब से मिलेगा ।यह फायदा उन्हीं किसानों के मिलेगा जिनका एग्रीस्टेक में पंजीयन है,डिजिटल क्राप सर्वे में धान बोने का रकबा दर्ज होने के साथ ही सत्यापित होना चाहिए।

साय सरकार की धान खरीदी की नई नीति से राज्य के किसानों को तो फायदा होगा ही सरकार को भी फायदा यह होगा कि दूसरे राज्यों से जो धान अवैध रूप से लाकर किसानों के नाम से बिचौलिए बेचा करते थे और फायदा किसानों को कम बिचौलियों को ज्यादा मिला करता था,उसमें कमी आएगी किसानों को कम धान बेचने पर ही पूरा 21 क्विंटल धान का बोनस मिलेगा तो वह बिचौलियों का धान अपने नाम से क्यों बेचेगा ।किसानों के नाम पर दूसरे राज्यों का धान बिकने के कारण राज्य सरकार को उसकी खरीदी,भंडारण और मिलिंग में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था, इस बार यह धान कम आने पर राज्य सरकार को पैसा बचेगा ।इसके अलावा ओडिशा सरकार ने भी विष्णन वर्ष 26-27 में एमएसपी व इनपुट सहायता मिलाकर किसानों के 3100 रुपए प्रति क्विंटल देने का फैसला किया है, इससे भी अब ओडिशा का धान छत्तीसगढ़ पहले कम आएगा ।झारखंड में भी सरकार ने बोनस 109 रुपए किया है, इसका असर भी यह होगा वहां से भी जो धान छत्तीसगढ़ आता था वह अब कम आएगा।

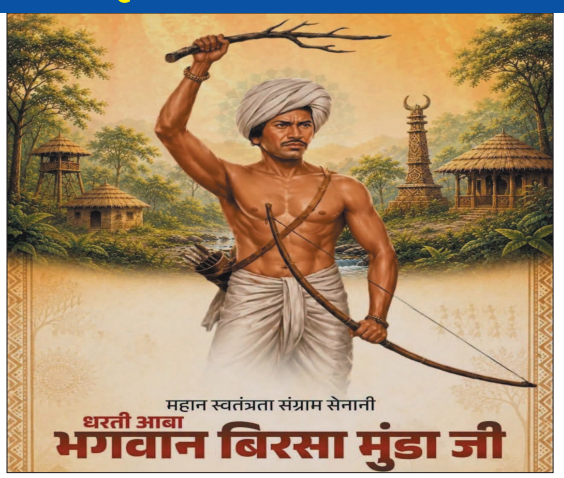
इससे साय सरकार को राजनीतिक रूप से भी फायदा होगा क्योंकि विपक्ष धान खरीदी के पहले से माहौल बनाने का प्रयास कर रहा था कि सरकार किसानों को उतना पैसा नहीं दे रही है जितना किसानों को कायदे से मिलना चाहिए ।वह आंकड़ों के जरिए यह बताने का प्रयास कर रहा था कि केंद्र सरकार जो एमएसपी हर साल बढ़ाती है, उसे सरकार को बोनस में कम करने नहीं देना चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि जितना एमएसपी हर साल बढ़ता है,सरकार बोनस में उतना पैसा कम किसानों को देती है,जबकि सरकार को उसे जोड़कर देना चाहिए। जबकि अपने समय में कांग्रेस सरकार खुद भी ऐसा करती थी ।विपक्ष तो मौका मिलते ही साय सरकार पर आरोप लगाएगा ही कि सरकार किसानों को कम पैसा दे रही है लेकिन किसानों को जब प्रति एकड़ कम धान होने पर बोनस 21 क्विंटल का ही मिलेगा तो उनको इस बात का एहसास होगा कि साय सरकार के समय उसको पहले से ज्यादा पैसा धान का मिल रहा है, एकमुश्त मिल रहा है और आसानी से मिल रहा है।

आदिवासी अस्मिता और साँस्कृतिक के रक्षक, महान क्राँतिकारी भगवान बिरसा मुंडा

धनंजय राठौर, संयुक्त संचालक, जनसंपर्क रायपुर

महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जनजातीय गौरव के प्रतीक एवं 'धरती आबा' जल, जंगल, जमीन एवं जनजातीय अस्मिता के सजग प्रहरी भगवान बिरसा मुंडा जी ने अन्याय और विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंककर आदिवासी समाज में स्वाभिमान और अधिकारों की चेतना जागृत की। अल्पायु में ही मातृभूमि, समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए दिया गया उनका सर्वोच्च बलिदान भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा। उनका साहस, नेतृत्व और जनसेवा का भाव आज भी हमें सामाजिक न्याय, स्वाभिमान और राष्ट्रहित के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा देता है।

स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय इतिहास में धरती आबा (धरती पिता) के नाम से पूजे जाने वाले बिरसा मुंडा मात्र एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि वे आदिवासी चेतना, स्वाभिमान और जल-जंगल-जमीन की रक्षा के सबसे बड़े प्रतीक थे। 19 वीं सदी के अंत में जब ब्रिटिश हुकूमत और जमींदार मिलकर आदिवासियों का शोषण कर रहे थे, तब बिरसा मुंडा ने एक ऐसी अलख जगाई जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी।



प्रारंभिक जीवन और चेतना का उदय

बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातु गांव में हुआ था। भारत सरकार द्वारा उनके जन्मदिन 15 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका बचपन चाईबासा के जंगलों और खेतों में बीता। पढ़ाई के लिए उन्होंने कुछ समय ईसाई मिशनरी स्कूल में दाखिला लिया, जहां उनका नाम बिरसा डेविड रखा गया। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने महसूस किया कि मिशनरी और ब्रिटिश व्यवस्था आदिवासियों की संस्कृति, भाषा और उनके पारंपरिक अधिकारों को नष्ट कर रही है। इसके बाद उन्होंने मिशनरी स्कूल छोड़ दिया और अपनी संस्कृति की रक्षा का संकल्प लिया।

बिरसा संप्रदाय और सामाजिक सुधार

क्रांति से पहले बिरसा मुंडा ने समाज को अंदर से मजबूत करने का काम किया। उन्होंने देखा कि अंधविश्वास और नशे के कारण आदिवासी समाज कमजोर हो रहा है। उन्होंने आदिवासियों को केवल एक ईश्वर (सिंगबोंगा) की पूजा करने की सलाह दी। सामाजिक बुराइयों का अंत करने शराबबंदी, पशु बलि के विरोध और स्वच्छता पर जोर दिया। उनके इन विचारों से प्रभावित होकर हजारों लोग उनके अनुयायी बन गए और लोग उन्हें प्यार से ह्नधरती आबाह्व कहने लगे।

उलगुलान (महान विद्रोह) की शुरुआत

उलगुलान मुंडारी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है महान उथल-पुथल या विद्रोह। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार की दिकु (बाहरी शोषक, जमींदार और सूदखोर) नीति के खिलाफ था, जो आदिवासियों की जमीनें छीन रहे थे। बिरसा मुंडा ने सिंहभूम और रांची के जंगलों में आदिवासियों को एकजुट किया और नारा दिया- अबुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू जाना (अर्थात अब हमारा राज शुरू हो गया है और महारानी का राज खत्म हो गया है)। मुंडा तीर- कमान और पारंपरिक हथियारों से लैस होकर ब्रिटिश चौकियों, थानों और जमींदारों पर गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से हमला करते थे। डोम्बारी पहाड़ी का युद्ध इस आंदोलन का एक ऐतिहासिक केंद्र बना।

1 अक्टूबर 1894 को बिरसा ने एक प्रखर युवा नेता के रूप में जन अधिकारों की रक्षा के लिए हुंकार भरी। उन्होंने अवैध जमींदारी के विरोध में लगान माफी आन्दोलन का सूत्रपात किया। अंग्रेजी सरकार ने इसे अपने शासन के विरुद्ध खुली चुनौती माना और 1895 में उन्हें बन्दी बना लिया। उन्हें हजारीबाग केन्द्रीय कारागार में 2 वर्ष के कारावास की दण्ड दिया गया। रिहाई के बाद उन्होंने शान्त बैठने के स्थान पर छोटानागपुर क्षेत्र में अकाल और महामारी से पीड़ित जनमानस की सेवा की। उनकी इस सेवा भावना ने उन्हें जन-जन का प्रिय बना दिया और लोग उन्हें 'धरती आबा' कहकर पुकारने लगे। उनका संघर्ष अब केवल आर्थिक नहीं, बल्कि जनजातीय स्वाभिमान और संस्कृति की रक्षा का महासंग्राम बन गया था। उन्होंने अबुआ दिशुम, अबुआ राज अर्थात हमारा देश, हमारा राज का अमर उद्घोष किया। इस नारे ने सोए हुए समाज में नई चेतना का संचार किया।

महानायक का बलिदान

1897 से 1900 के मध्य उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष आरम्भ किया। इसके लिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। उनके बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज अधिकारी और शोषक वर्ग भयभीत हो उठा। 24 दिसम्बर 1899 को यह आन्दोलन अत्यन्त उग्र हो गया। पुलिस थानों पर तीरों से प्रहार किए गए। इस संघर्ष के दौरान अंग्रेजी सेना ने डोम्बारी बुरु पहाड़ी पर निहत्थे जनजातीयों पर बर्बरतापूर्वक गोलीबारी की। जनजातीयों ने अदम्य साहस का परिचय दिया,किन्तु उनके तीर और कमान अंग्रेजों के आधुनिक हथियारों और गोलियों के सम्मुख अधिक समय तक टिक नहीं सके।

ब्रिटिश सेना आधुनिक हथियारों से लैस थी, फिर भी बिरसा मुंडा की रणनीतियों के सामने उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। आखिरकार, अंग्रेजों ने चाल चली और बिरसा मुंडा पर इनाम रख दिया। मार्च 1900 में चक्रधरपुर के जामकोपाई जंगल से सोते समय उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। मात्र 24 वर्ष की आयु में 9 जून 1900 को रांची जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में (अंग्रेजों के अनुसार हैजे के कारण) उन्होंने अंतिम सांस ली। लेकिन इतिहासकारों और उनके अनुयायियों का मानना है कि उन्हें अंग्रेजों द्वारा जेल में धीमा जहर दिया गया था। उनकी शहादत के बाद अंग्रेजों को आदिवासियों की जमीन की रक्षा के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 (Chota Nagpur Tenancy Act, 1908 - CNT Act) कानून बनाना पड़ा, जिसने बाहरी लोगों को आदिवासी जमीन खरीदने से रोका।

वास्तव में, ब्रिटिश भू-राजस्व नीति, मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव, 'खुटकट्टी प्रणाली' का विनाश और 'दिकू' अर्थात बाहरी शोषकों का अनैतिक हस्तक्षेप ही इस विद्रोह के मूल में था। मुंडा जनजातियों का एक और नारा अत्यन्त प्रसिद्ध हुआ: अबुआ राज एटेर जना, महारानी राज तुंदु जना जिसका अर्थ था कि अब हमारा राज स्थापित हो और ब्रिटिश महारानी का राज समाप्त हो। 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की अल्पायु में राँची जेल में बिरसा मुंडा का निधन हो गया। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने मृत्यु का कारण हैजा बताया, किन्तु जनमानस और कई इतिहासकारों ने इसे सन्दिग्ध माना है। कुछ विवरणों में उन्हें विष दिए जाने की आशंका भी व्यक्त की गई है।

धरती आबा बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि जब हम अपनी संस्कृति, अस्मिता और अधिकारों की हो, तो संसाधनों की कमी कभी भी आपके हौसलों को डिगा नहीं सकती। भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय समाज की अस्मिता के संरक्षण एवं जनमानस के अदम्य संघर्ष और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिये अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध उनके जनआंदोलन ने जनजातीय गौरव की अमिट ज्योति प्रज्वलित की। उनके साहस, समाज व संस्कृति के लिए अनन्य समर्पण के प्रतिमान आने वाली पीढ़ी के लिए त्याग और वीरता की अद्वितीय शौर्यगाथा हैं।

आजादी के 75 वें वर्ष के अवसर पर 2021 में केंद्र सरकार ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की सेवाओं को मनाने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित की। भारत ही नहीं बल्कि जनजाति समुदाय बिरसा मुंडा की जयंती बड़ी धूमधाम व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और उनके इस योगदान को भारतीय समाज प्रेरणा दायक मानता हैं। ऐसे ही महानायक हुवे बिरसा मुँडा। उनके जीवन में कुछ ऐसी विलक्षण घटनाएँ घटीं जिससे लोग उन्हे असाधारण कहते हैं और भगवान का दर्जा देते हैं, उनकी पूजा करते हैं।

जड़ों की ओर लौटने और इतिहास के महानायकों के पुण्य स्मरण का महापर्व

ताराशंकर सिन्हा, सहायक संचालक, रायपुर

15 नवंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, एक संकल्प है जब भारत के इतिहास की बात होती है तो अक्सर दिल्ली के महलों, मुगलों के युद्धों और अंग्रेजों की चालों तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन भारत का असली इतिहास जंगलों, पहाड़ों और नदियों के किनारे लिखा गया है। वह इतिहास उन आदिवासियों ने लिखा है जिन्होंने कभी किताबों में अपना नाम नहीं मांगा, लेकिन अपनी मिट्टी के लिए प्राण दे दिए। उन्हीं वीरों को याद करने के लिए केन्द्र सरकार के आह्वान पर वर्ष 2021 से हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है।

धरती आबा बिरसा मुंडा से शुरू हुई यह यात्रा-

जनजातीय गौरव दिवस के लिए 15 नवंबर का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1875 में वर्तमान झारखंड के उलिहातु गांव में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। भगवान बिरसा मुंडा सिर्फ 25 साल जिए, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की नींदें उड़ा दी थीं। उन्होंने नारा दिया था – अबुआ दिशोम रे अबुआ राज यानी हमारे देश में हमारा ही राज होगा। अंग्रेजों ने उन पर जमींदारी, बेगार और धर्मांतरण का जो तंत्र थोपा था, उसके खिलाफ बिरसा ने उलगुलान यानी महाविद्रोह का बिगुल फूंका। आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं, धरती आबा कहते हैं। 2021 में जब केंद्र सरकार ने उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया, तो ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, ये इतिहास के सच के साथ न्याय था। भुला दिए गए महानायक बिरसा मुंडा अकेले नहीं थे। भारत की आजादी की लड़ाई में आदिवासी समाज का योगदान सबसे बड़ा और सबसे कम दर्ज हुआ है। तिलका मांझी ने 1784 में ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जब 1857 की क्रांति का नाम भी किसी ने नहीं सुना था। सिद्धो-कान्हो ने संथाल हूल का नेतृत्व किया। रानी गाइदिन्ल्यू मात्र 13 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो गईं। अल्लूरी सीताराम राजू, टंट्या भील, रानी दुर्गावती, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडाधूर, शहीद गैंद सिंह- ये नाम इतिहास की किताबों के हाशिये पर रह गए। जनजातीय गौरव दिवस इन सभी नामों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास है जो सिर्फ अतीत नहीं, वर्तमान भी है।

जनजातीय परम्पराओं को शिखर तक ले जाने छत्तीसगढ़ सरकार निभा रही अहम भूमिका –

छत्तीसगढ़ को यूं ही आदिवासियों का प्रदेश नहीं कहा जाता है। यहां की 32 प्रतिशत से ज्यादा आबादी जनजातीय समाज की है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक, जशपुर से लेकर कोरबा तक, इस प्रदेश की आत्मा आदिवासी संस्कृति में बसती है। इसलिए जब 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ के लिए यह सिर्फ एक शासकीय कार्यक्रम नहीं होता, बल्कि अपनी पहचान का उत्सव होता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले तीन वर्षों में आदिवासी अस्मिता, विकास और स्वाभिमान को पहचान दिलाने अनवरत प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस पर छत्तीसगढ़ के अपने जनजातीय नायकों को सामने लाया। बिरसा मुंडा के साथ-साथ यहां शहीद वीर नारायण सिंह को याद किया जाता है। सोनाखान के इस वीर ने 1857 से पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। सरकार ने रायपुर में उनकी भव्य प्रतिमा, संग्रहालय और उनकी जयंती पर राज्य स्तरीय आयोजन शुरू किए। इसी तरह शहीद गुंडाधुर, शहीद गैंद सिंह, रानी दुर्गावती जैसे नायकों पर किताबें, नाटक और प्रदर्शनी आयोजित की जा रही हैं, ताकि क्यों सिर्फ किताबों में ही नहीं, अपने गांव-शहर में इतिहास के वास्तविक नायकों के बारे में जान सकें।

छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्यप्रदेश में आज भी करोड़ों आदिवासी भाई-बहन अपनी भाषा, बोली, पारम्परिक नृत्य, पुरखों से पूजे जा रहे देवी-देवता, अपनी खेती को बचाए हुए हैं। बस्तर का पंडुम, सरगुजा का करमा नृत्य, जशपुर का सुआ नृत्य सिर्फ लोक मनोरंजन नहीं हैं, ये हजारों साल पुरानी सभ्यता की जीवित धरोहर हैं। जनजातीय गौरव दिवस हमें यह सिखाता है कि विकास का मतलब आदिवासी को शहर जैसा बनाना नहीं है, बल्कि आदिवासी की पहचान को बचाते हुए उसे आगे बढ़ाना है। जनजातीय गौरव दिवस की असली श्रद्धांजलि तब होगी जब आदिवासी बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा का मौका दें। उनके जल, जंगल, जमीन के अधिकारों का सम्मान करें। उनके उत्पादों- महुआ, तेंदूपत्ता, बांस शिल्प, लौह शिल्प को समुचित बाजार दें। उन्हें पिछड़ा न कहकर, भारत का मूल निवासी और गौरव कहें। इतिहास गवाह है कि जिस देश ने अपने जंगल के बेटों को भुला दिया, तो अपनी वास्तविक जड़ों से कोसों दूर हो गया। इसलिए 15 नवंबर को सिर्फ बिरसा मुंडा को याद नहीं करना है, बल्कि यह संकल्प दोहराना है कि हम आदिवासी गौरव को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि जब तक आदिवासी गौरवान्वित नहीं होगा, तब तक भारत गौरवान्वित नहीं हो सकता।

कामयाबी की दौड़ में सिमटता बच्चों का बचपन

राजेश जैन

किसी देश का भविष्य सिर्फ इस बात से तय नहीं होता कि उसके बच्चे कितने बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, कितने नंबर लाते हैं या कितनी अच्छी नौकरी पाते हैं। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि वे कितने खुश हैं, कितनी स्वतंत्रता से सोच पाते हैं और कितने संवेदनशील इंसान बनकर बड़े हो रहे हैं। बच्चों की सफलता का आकलन करते समय अक्सर उनकी उपलब्धियां गिनी जाती हैं, लेकिन उनके बचपन की गुणवत्ता पीछे छूट जाती है। सुबह स्कूल जाते बच्चे के कंधे पर भारी बस्ता है। दिमाग में परीक्षा की चिंता और शाम को कोचिंग की तैयारी। घर लौटने के बाद होमवर्क पूरा करना है। दूसरी ओर, उसी उम्र का एक बच्चा किसी दुकान, ढाबे या वर्कशॉप पर काम कर रहा है। एक के पास अच्छे स्कूल और तमाम सुविधाएं हैं, तो दूसरा दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। दोनों एक ही देश के बच्चे हैं, लेकिन उनके हिस्से का बचपन बिल्कुल अलग है।

14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हुए इन दोनों तस्वीरों को साथ रखकर देखना जरूरी है। हम बच्चों को देश का भविष्य बताते हैं और उनके लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य व सुविधाओं की बात करते हैं, लेकिन उनके वर्तमान को बेहतर बनाने की चिंता उतनी ही गंभीरता से नहीं करते। बचपन केवल बड़ा होने और कामयाब बनने की तैयारी का समय नहीं है। यह खेलने, सीखने, सवाल पूछने, गलतियां करने और अपनी रुचि के मुताबिक दुनिया को समझने का दौर है। दुर्भाग्य से आज यही सहजता लगातार कम होती जा रही है।

उम्मीदों के बोझ तले दबे बच्चे

बचपन खेलने, नई चीजें जानने और अपनी दुनिया बनाने की उम्र है। लेकिन आज इस उम्र पर पढ़ाई और कामयाबी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। बच्चा अच्छे नंबर लाए, प्रतियोगिताओं में आगे रहे, हर गतिविधि में अव्वल हो और कम उम्र में ही अपने करियर का रास्ता तय कर ले। अभिभावकों की ये अपेक्षाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब बच्चे की हर गतिविधि का उद्देश्य सिर्फ जीतना और दूसरों से आगे निकलना रह जाता है।

कई घरों में बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करना आम बात है। पड़ोसी का बच्चा कितने नंबर लाया, किस स्कूल में पढ़ता है और किस प्रतियोगिता में चुना गया। इन सवालों के बीच बच्चे की अपनी रुचि और क्षमता पीछे छूट जाती है। वह धीरे-धीरे वही करने लगता है, जिसकी उससे अपेक्षा की जाती है।

इसका असर तब सामने आता है, जब बच्चा परीक्षा में कम नंबर लाता है या किसी प्रतियोगिता में पीछे रह जाता है। उसे गलती सुधारने और दोबारा कोशिश करने का हौसला देने के बजाय कई बार निराशा और ताने मिलते हैं। नतीजतन, असफलता उसके लिए सीखने का अवसर नहीं, बल्कि डर का कारण बन जाती है। बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देना और पीछे रह जाने का डर दिखाकर दौड़ाना दो अलग बातें हैं। इस अंतर को समझना परिवारों के लिए जरूरी है।

पढ़ाई के साथ सीखने की खुशी भी जरूरी

शिक्षा का अधिकार कानून छह से चौदह वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार देता है। नई शिक्षा नीति में भी रटने के बजाय समझकर सीखने, रचनात्मकता और व्यावहारिक ज्ञान पर जोर दिया गया है। इसके बावजूद स्कूलों में पढ़ाई का बड़ा हिस्सा अब भी परीक्षा और अंकों के इर्द-गिर्द घूमता है।

पाठ्यक्रम पूरा करने और अच्छे परिणाम देने के दबाव में खेल, कला, संगीत और बच्चों की जिज्ञासा के लिए जगह कम हो जाती है। बच्चे को सवाल पूछने और अपनी बात रखने के बजाय सही जवाब याद करने की आदत पड़ने लगती है। जबकि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि सोचने, समझने और सवाल करने की क्षमता विकसित करना है। जिस पढ़ाई में जिज्ञासा और सीखने की खुशी न हो, वह बच्चे के सर्वांगीण विकास का आधार नहीं बन सकती।

मोबाइल के साय बदलती बचपन की दुनिया

आज बच्चों का बचपन मोबाइल और इंटरनेट से भी गहराई से प्रभावित हो रहा है। तकनीक ने सीखने और दुनिया को समझने के नए रास्ते खोले हैं। बच्चा घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने की जानकारी हासिल कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी सीखने के अवसरों का विस्तार किया है। लेकिन इसके साथ यह चुनौती भी है कि कहीं मोबाइल बच्चों की जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा तो नहीं बनता जा रहा कि वास्तविक दुनिया पीछे छूट रही है। मोबाइल पर गेम, वीडियो और सोशल मीडिया बच्चों का काफी समय ले रहे हैं। दोस्तों के साथ खेलना, आमने-सामने बातचीत करना और बाहरी गतिविधियों में शामिल होना कम हो रहा है। सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोअर्स की संख्या भी बच्चों की पहचान और आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती है। समस्या तकनीक नहीं, बल्कि उसका जरूरत से ज्यादा और बिना समझ के इस्तेमाल है।

बच्चों को इंटरनेट से दूर रखना इसका समाधान नहीं है। उन्हें यह समझाना जरूरी है कि ऑनलाइन मिलने वाली हर जानकारी सही नहीं होती। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी और अनुचित सामग्री से बचने की समझ भी उनकी शिक्षा का हिस्सा होनी चाहिए। अभिभावकों की भूमिका केवल मोबाइल देने या छीनने तक सीमित नहीं रह सकती। उन्हें बच्चों की डिजिटल दुनिया को समझने के साथ उनके साथ समय भी बिताना होगा। परिवार से बातचीत, दोस्तों के साथ खेल और बाहर की दुनिया के अनुभव भी बच्चे के विकास के लिए उतने ही जरूरी हैं।

अवसरों की असमानता में बंटा बचपन

भारतीय समाज में बचपन की सबसे बड़ी विडंबना ओं में से एक अवसरों की असमानता है। एक तरफ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें महंगे स्कूल, स्मार्ट क्लास, निजी ट्यूटर और आधुनिक संसाधन उपलब्ध हैं। दूसरी तरफ ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए अच्छी किताबें, पौष्टिक भोजन और नियमित रूप से स्कूल जाना भी आसान नहीं है।

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को कई बार कम उम्र में ही काम करना पड़ता है। इसके पीछे गरीबी के साथ शिक्षा तक सीमित पहुंच और परिवार की मजबूरियां भी जिम्मेदार हैं। ऐसे में केवल यह कहना पर्याप्त नहीं कि हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि हर बच्चे के पास पढ़ाई जारी रखने के लिए आवश्यक संसाधन और अनुकूल माहौल हो।

शिक्षा मंत्रालय की यूडीआईएसई प्लस 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार देश के 67.4 प्रतिशत स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। यानी करीब एक तिहाई स्कूलों में अब भी इंटरनेट नहीं है। कंप्यूटर की सुविधा वाले स्कूलों का अनुपात 69.9 प्रतिशत है। डिजिटल शिक्षा के विस्तार के दौर में ये आंकड़े बताते हैं कि तकनीक तक पहुंच के मामले में अभी भी सभी बच्चों को समान अवसर नहीं मिल पाए हैं।

सुरक्षा के मोरोसे पर खरे उतरना जरुरी

शिक्षा और सुविधाओं के साथ बच्चों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। घर, स्कूल, सार्वजनिक स्थान और इंटरनेट; कहीं भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बाल शोषण, हिंसा, अपहरण और ऑनलाइन अपराध की घटनाएं इस जिम्मेदारी को और गंभीर बनाती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया-2024 रिपोर्ट के अनुसार देश में बच्चों के खिलाफ अपराध के 1,87,702 मामले दर्ज किए गए। वर्ष 2023 में यह संख्या 1,77,335 थी। यानी एक साल में करीब 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इनमें अपहरण और पॉक्सो कानून के तहत दर्ज अपराध बड़ी संख्या में शामिल थे। यह आंकड़ा पुलिस में दर्ज मामलों का है, इसलिए इसे बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की पूरी तस्वीर नहीं माना जा सकता। कई घटनाएं सामने ही नहीं आ पातीं।

चिंता की बात यह भी है कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले कई बार उनके परिचित या भरोसे के दायरे में होते हैं। ऐसे में बच्चों को केवल सुरक्षा के नियम बताना पर्याप्त नहीं है। उन्हें यह भरोसा देना भी जरूरी है कि उनके साथ कुछ गलत होने पर उनकी बात सुनी जाएगी और उन्हें चुप रहने या अपनी गलती मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। स्कूलों में गोपनीय शिकायत व्यवस्था, काउंसलिंग और बाल सुरक्षा से जुड़े नियमों का प्रभावी पालन होना चाहिए।

बच्चों की जिंदगी पर बड़ों के सपनों का कब्जा

बच्चों पर बढ़ते दबाव के पीछे परिवार की सोच भी एक बड़ी वजह है। हर अभिभावक चाहता है कि उसका बच्चा उससे आगे बढ़े और बेहतर जिंदगी जिए। लेकिन कई बार इसी चाहत में वे बच्चों के लिए पहले से तय कर देते हैं कि उन्हें क्या बनना है। कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर तो कोई प्रशासनिक अधिकारी। इस पूरी प्रक्रिया में बच्चे की अपनी इच्छा और रुचि पीछे छूट जाती है।

खेलना, चित्र बनाना, संगीत सीखना या नई चीजें तलाशना भी बच्चों की जिंदगी का जरूरी हिस्सा है। हर शौक को करियर और कमाई से जोड़कर देखना उचित नहीं है। बच्चों को रास्ता दिखाना अभिभावकों की जिम्मेदारी है, लेकिन उनकी जिंदगी का हर फैसला खुद करना नहीं। हर बच्चा अलग होता है। उसकी प्रतिभा, रुचि और सीखने की गति भी अलग हो सकती है। उसे अपनी पसंद पहचानने और गलतियों से सीखने का अवसर मिलना चाहिए। अपनी बात कहने और उम्र के अनुरूप फैसलों में भागीदारी का मौका मिलने से उसका आत्मविश्वास भी मजबूत होता है।

योजनाओं से आगे बढ़कर जमीन पर बदलाव

बच्चों की शिक्षा, पोषण और सुरक्षा के लिए देश में कई कानून और योजनाएं हैं। शिक्षा का अधिकार कानून, आंगनबाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और पीएम पोषण जैसी योजनाओं से लाखों बच्चों को लाभ मिला है। लेकिन किसी योजना की सफलता केवल इस बात से तय नहीं हो सकती कि कितने बच्चों के नाम लाभार्थियों की सूची में दर्ज हैं। असली कसौटी यह है कि क्या बच्चे कुपोषण से बाहर आ रहे हैं, क्या उन्हें स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है, क्या लड़कियां अपनी पढ़ाई पूरी कर पा रही हैं और क्या हर बच्चा हिंसा व शोषण से सुरक्षित है। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के साथ खेल के मैदान, पुस्तकालय और सुरक्षित सार्वजनिक स्थान बढ़ाने होंगे। बच्चों से जुड़े फैसले लेते समय उनकी राय को भी महत्व देना होगा। स्कूलों और स्थानीय निकायों में ऐसे मंच विकसित किए जा सकते हैं, जहां बच्चे अपनी समस्याएं और सुझाव रख सकें। जिनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं, उन बच्चों की आवाज भी उन नीतियों में शामिल होनी चाहिए।

###



'जीवन भीमा योजना' का ट्रेलर रिलीज, डबल रोल में फिर कॉमेडी करते दिखे अरशद

फिल्म 'जीवन भीमा योजना' का ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। फिल्म में अरशद वारसी डबल रोल में नजर आने वाले हैं। ट्रेलर में कॉमेडी का जबरदस्त तड़का है। वहीं संजीदा शेख भी यहां 'धमाल 4' के बाद एक बार फिर से कॉमेडी करती नजर आएंगी।

फिल्म 'जीवन भीमा योजना' में अरशद को दोहरे किरदार 'जीवन' और 'भीमा' के रूप में देखा जाएगा। इसके साथ ही ट्रेलर में कई किरदार और उनके बीच के कंफ्यूजन को दिखाया गया है। ट्रेलर के पहले सीन में लगता है जैसे कोई किसी को मारने की कोशिश कर रहा है। दूसरे सीन में जीवन (अरशद) की पत्नी योजना (संजीदा) पति के निधन पर नाटकीय अंदाज में रोती दिखाई देती हैं। इस सीन में पता चलता है कि जीवन ने एक करोड़ रुपये का बीमा कराया था। वहीं अपने निधन से पहले वह 1 करोड़ का दूसरी बीमा भी कराकर गए थे। इसके बाद एंट्री होती है विनायक (विजय राज) की, जो पैसे के लिए संजीदा के पीछे पड़े हुए हैं। इसी दौरान उनका सामना भीमा (अरशद) से होता है, जिसे वह जीवन समझते हैं। फिर होता है कॉमेडी में लिपटा एक्शन और किरदारों के बीच तगड़ा कंफ्यूजन। फिल्म को लेकर क्या बोले निर्देशक? हाल ही में फिल्म पर बात करते हुए निर्देशक अभिषेक डोगरा ने कहा था, 'जीवन भीमा योजना उन आम लोगों की कहानी है, जो एक असाधारण फैसला लेते हैं और फिर पूरी फिल्म उस एक फैसले की कीमत चुकाते हुए नजर आते हैं। फिल्म का जॉनर डार्क कॉमेडी है, लेकिन इसकी भावनात्मक जड़ें बेहद मानवीय हैं। अरशद ने दोनों किरदारों को जिस सटीकता के साथ जीवंत किया, उसने सेट पर हमें भी लगातार हैरान किया।'

कब रिलीज होगी फिल्म

अभिषेक डोगरा के निर्देशन और स्टारबीम वेंचर्स लिमिटेड के बैनर तले बनी इस फिल्म में अरशद वारसी, संजीदा शेख, विजय राज, ब्रजेन्द्र काला, पूजा चोपड़ा, अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

फिल्म इंडस्ट्री में काम करना हमेशा एक सौभाग्य जैसा लगा



अभिनेत्री राशि खन्ना, जिन्हें हाल ही में फिल्म '120 बहादुर' में विशेष भूमिका में देखा गया था, ने भारतीय फिल्म उद्योग में अपने 13 साल पूरे कर लिए हैं। अभिनेत्री ने कहा कि 'मद्रास कैफे' से अपने करियर की शुरुआत के बाद से उन्हें ऐसा लगता है कि समय पंख लगाकर उड़ गया क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने काम को एक विशेषाधिकार के रूप में देखा है। यह फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी और इसी ने राशि खन्ना के लिए चार अलग-अलग फिल्म उद्योगों में काम करने का रास्ता खोला। इसके बाद वह देश की चर्चित फिल्मों और परियोजनाओं का हिस्सा बनीं।

अपने सफर को याद करते हुए राशि ने कहा, 'तेरह साल एक लंबा समय होता है लेकिन यह बहुत तेजी से बीत गया क्योंकि काम करना कभी विशेषाधिकार लगना बंद नहीं हुआ। 'मद्रास कैफे' को याद करने पर मुझे एहसास होता है कि मैंने शुरुआत क्यों की थी। इस फिल्म ने मुझे ऐसी कहानियां कहने का अवसर दिया जो मेरे लिए मायने रखती हैं, और मैं उन सभी सहयोगियों की आभारी हूं जिन्होंने इस सफर में मेरा साथ दिया।' अपने डेब्यू के बाद से राशि ने हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम सिनेमा में काम करते हुए एक मजबूत पहचान बनाई है। उनकी पीढ़ी के चुनिंदा कलाकारों में से वह एक हैं, जिन्होंने चारों फिल्म उद्योगों में अपनी मौजूदगी कायम रखी है। यह विविधता संयोग नहीं बल्कि उनके सोच-समझकर लिए गए फैसलों का परिणाम है, जिसने उन्हें एक उभरती हुई अभिनेत्री से पैन-इंडिया स्टार तक पहुंचाया। वर्तमान में अभिनेत्री राज और डीके की लोकप्रिय वेब सीरीज 'फर्जी' के दूसरे सीजन की शूटिंग कर रही हैं। इसमें वह एक बार फिर आरबीआई अधिकारी मेघा व्यास की भूमिका में नजर आएंगी। इस सीरीज में उनके साथ शाहिद कपूर और विजय सेतुपति भी दिखाई देंगे। राज और डीके द्वारा निर्मित और निर्देशित यह क्राइम थ्रिलर एक ऐसे कलाकार की कहानी है, जो आर्थिक परेशानियों से निकलने के लिए नकली नोट बनाने के रास्ते पर चल पड़ता है। राशि खन्ना जल्द ही तमिल एक्शन थ्रिलर 'धर्मन' में सुपरस्टार रजनीकांत के साथ नजर आएंगी। इसके अलावा वह निर्देशक अनीस बज्मी की अगली कॉमेडी-ड्रामा फिल्म में अभिनेता अक्षय कुमार के साथ भी दिखाई देंगी।

'द रेवोल्यूशनरीज' में रोहित सराफ का शानदार बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन

बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द रेवोल्यूशनरीज' का ट्रेलर रिलीज हो गया है और इसमें रोहित सराफ पूरी ताकत के साथ नजर आ रहे हैं। फिल्म में वह सचिंद्रनाथ सान्याल का किरदार निभा रहे हैं। इस किरदार के जरिए रोहित एक ऐसे दौर और भूमिका में नजर आएंगे, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं निभाया है। यही बात फिल्म को और खास बनाती है। रोहित ने अपने किरदार को बेहतर तरीके से निभाने के लिए अपनी बॉडी और लुक में भी शानदार बदलाव किया है। उनका बदला हुआ शारीरिक रूप और गंभीर अंदाज उनके किरदार को और ज्यादा प्रभावशाली बनाता है। ऐसा लगता है कि रोहित ने सिर्फ यह फिल्म साइन नहीं की है, बल्कि अपने अभिनय में कुछ नया और बड़ा करने का फैसला किया है। ट्रेलर में रोहित के जबरदस्त एक्शन और फाइटिंग सीन्स भी देखने को मिलते हैं। उनके एक्शन सीन काफी दमदार हैं और उनके किरदार की ताकत और जुनून को दिखाते हैं। उनकी एक्टिंग में गुस्सा, जोश और संघर्ष साफ नजर आता है। 'द रेवोल्यूशनरीज' का ट्रेलर रोहित सराफ का एक बिल्कुल नया और बदला हुआ रूप दिखाता है। यह उनके करियर के सबसे अलग और बड़े बदलावों में से एक माना जा सकता है। यह पीरियड ड्रामा उन बहादुर युवा भारतीय क्रांतिकारियों की कहानी पर आधारित है, जो मानते थे कि ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए हथियार उठाकर लड़ना जरूरी था।





प्रिया भवानी शंकर ने 'इरुमुड़ी' के सफर को बताया बेहद खास

दक्षिण भारतीय फिल्मों की जानी-मानी अभिनेत्री प्रिया भवानी शंकर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'इरुमुड़ी' को लेकर चर्चा में हैं। निर्देशक शिव निर्वाण की इस फिल्म में वह अभिनेता रवि तेजा के साथ मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। वह फिल्म में कावेरी का किरदार निभा रही हैं, जो एक अच्छी पत्नी और मां है। अपने किरदार को लेकर उन्होंने कहा कि कावेरी उनके लिए बहुत खास है। प्रिया भवानी शंकर ने कहा, ''कावेरी मेरे लिए बहुत खास किरदार रहा है। जब मैंने कहानी सुनी और शिव निर्वाण की बनाई भावनाओं की दुनिया को समझा, तो मुझे ऐसी सच्ची और दमदार कहानी का हिस्सा बनकर बहुत खुशी हुई। 'इरुमुड़ी कद्दू' के रिश्तों में गर्मजोशी और भावनाएं हैं। इसी वजह से कावेरी का किरदार निभाने का सफर मेरे लिए बहुत खास रहा.' फिल्म में रवि तेजा के साथ काम करने का मौका मिलने पर भी प्रिया काफी खुश नजर आईं। उन्होंने कहा, ''रवि तेजा के साथ काम करना मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा। उनके काम करने के तरीके में सहजता है। इसकी वजह से हमारे साथ वाले सीन काफी आरामदायक और मजेदार रहे। डायरेक्टर को हर किरदार की भावनाओं को लेकर बहुत साफ समझ थी और उनके विजन के हिसाब से काम करना मेरे लिए बहुत खूबसूरत अनुभव रहा।''

उन्होंने कहा, ''इस सफर के दौरान मैंने अपने साथी कलाकारों और टीम के साथ बहुत सारी यादें बनाईं। शूटिंग के दौरान कई मज़ेदार पल आए, खूब हंसी-मजाक हुआ और टीम के बीच ऐसी बातें भी हुईं, जो मेरे लिए निजी याद बन गईं।'' अभिनेत्री ने कहा, ''जब हमने आखिरकार फिल्म की शूटिंग पूरी की तो मुझे एहसास हुआ कि हम इस सफर से फिल्म के अलावा भी कितना कुछ अपने साथ लेकर जा रहे हैं। हमने बहुत सारे सीन शूट किए, हजारों यादें बनाईं, और साथ में हंसी के बहुत सारे पल बिताए। यह उन यात्राओं में से एक थी, जहां जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, वे आपकी यादों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। यह सच में बहुत खूबसूरत सफर रहा।''



इंसान की सबसे ज्यादा ग्रोथ मुश्किल परिस्थिति में होती है

'सेक्रेड गेम्स', 'द ट्रायल' और 'सन ऑफ सरदार 2' जैसी सीरीज और फिल्मों में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस कुब्रा सैत पर्दे पर जहां बिंदास किरदारों के लिए जानी जाती हैं, वहीं निजी जिंदगी में भी उन्हें खतरों से खेलना पसंद है। एडवेंचर में कुब्रा की जान बसती है, इसलिए वह कभी तंजानिया के किलिमंजारो पर्वत पर ट्रैकिंग करने पहुंच जाती हैं, तो कभी दुनिया की चौथी बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र में लहरों से खेलने यानी रिवर राफ्टिंग करने। कुब्रा के मुताबिक, उन्हें खुद को ऐसी असहज परिस्थितियों में डालना पसंद है, क्योंकि इससे उन्हें खुद को जानने का मौका मिलता है।

एडवेंचर ट्रिप से बेहतर टीचर नहीं

बकौल कुब्रा, 'मुझे लगता है कि इंसान की सबसे ज्यादा ग्रोथ तब होती है, जब आप असहज परिस्थिति में होते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर होते हैं, इसलिए मुझे खुद को ऐसी परिस्थितियों में डालना अच्छा लगता है क्योंकि इन चीजों से मैं आगे बढ़ पाती हूं। मतलब, जब आप ऐसे ट्रिप्स पर जाते हैं, जहां आपके पास सोने के लिए बेड नहीं होता है। आप टेंट और स्लीपिंग बैग्स में सोते हैं। फिर सुबह साढ़े 7 बजे अपना पूरा बैग पैक करके आपको टेंट से बाहर निकलना है और आपकी सारी उंगलियां सारी सूजी हुई हैं। उस वक्त आप बस यही कोशिश करते हैं कि प्लीज मेरे मुंह से गाली न निकले और मैं 15 मिनट में बैग पैक कर निकल जाऊं तो जो धैर्य आपमें आता है, ये सब बहुत सीख है भाई।'

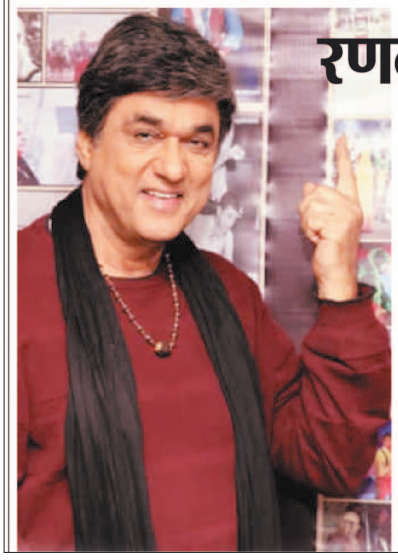
कुब्रा ने आगे कहा, 'मेरा मानना है कि जब आप जीवन को ऐसे अनुभव करते हैं, तभी एक्टर बन सकते हैं। अगर हर चीज आपके साथ अच्छी रहे कि घर गए, खाना बन गया, सब काम हो गया, तो क्या ही मजा है। इसलिए मैं हर साल ऐसी ट्रिप पर जाती हूं, क्योंकि मुझे खुद को जानने का मौका मिलता है और खुद को जानने का सफर बहुत लंबा है। मुझे लगता है कि मैंने अभी शुरू किया है।'

कुब्रा सैत का परिवार और करियर

कुब्रा सैत की निजी जिंदगी की बात करें, तो वह कर्नाटक के बेंगलुरु शहर एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुईं। उनके पिता का नाम मोहम्मद हदीद हैं और मां यास्मिन सेठ एक बिजनेसवुमन हैं। कुब्रा सैत ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी। वह दुबई की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में बतौर अकाउंट मैनेजर भी कार्यरत रहीं।

2011 में सलमान की फिल्म से करियर शुरू

कुब्रा ने साल 2009 में 'मिस वर्ल्ड वाइड ब्यूटी' कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। 2011 में उन्होंने सलमान खान स्टारर 'रेडी' से एक्टिंग डेब्यू किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुब्रा सैत को 2013 में एशिया की सबसे शानदार पब्लिक स्पीकर के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है।



रणवीर सिंह पर फिर बोले मुकेश खन्ना वो चाहें तो विलन बन जाएं

मुकेश खन्ना ने हाल ही में अपने आइकोनिक किरदार शक्तिमान पर खुलकर बात की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह बड़े पर्दे पर 'शक्तिमान' के किरदार के लिए रणवीर सिंह को सही विकल्प नहीं मानते।

'शक्तिमान' पर फिल्म बनाने की चर्चा काफी समय से चल रही है। इस फिल्म के लिए रणवीर सिंह का नाम भी सामने आया था। लेकिन मुकेश खन्ना ने इस कास्टिंग पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें अब 'शक्तिमान' के किरदार से आगे बढ़ जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा, 'मैं आगे क्यों बढ़ूं? मैंने शक्तिमान बनाया है।' मुकेश खन्ना ने बताया कि उन्होंने सोनी इंडिया और सोनी इंटरनेशनल को अपनी मंजूरी के बिना फिल्म पर आगे बढ़ने से रोक दिया है। उनके मुताबिक, उन्हें पहले एक पेमेंट मिल चुकी थी, लेकिन जब मेकर्स ने कुछ ऐसी शर्तें रखीं जो उनकी शुरुआती सहमति से अलग थीं, तो उन्होंने अगला चेक रोक दिया। उन्होंने कहा, 'इसमें कोई शक नहीं कि कमर्शियल तौर पर मैं बेवकूफी कर रहा हूं। मैंने लाखों का नहीं, करोड़ों का चेक ठुकराया है।' एक्टर ने बताया कि उनके ऑफिस में मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी थी कि पैसे ले लें और बाद में इस मामले को देखेंगे। किन मुकेश खन्ना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उनके लिए पैसा नहीं बल्कि उनके सिद्धांत ज्यादा जरूरी हैं। शक्तिमान को डिस्को में नाचते नहीं देख सकता मुकेश खन्ना को इस बात की भी चिंता है कि फिल्म को मॉडर्न बनाने के नाम पर 'शक्तिमान' के किरदार में जरूरत से ज्यादा बदलाव न कर दिए जाएं। उन्होंने कहा कि कल फिल्म में शक्तिमान को डिस्को में नाचते हुए दिखाया जा सकता है और उसके बाद कुछ और भी ऐसा किया जा सकता है, जो इस किरदार की असली पहचान से मेल नहीं खाता।

शक्तिमान के लिए रणवीर की इमेज सही नहीं

मुकेश खन्ना ने बताया कि रणवीर ने करीब तीन घंटे तक उन्हें शक्तिमान के किरदार के लिए मनाने की कोशिश की थी। मुकेश खन्ना ने रणवीर की एनर्जी की तारीफ भी की। उन्होंने बताया कि रणवीर बातचीत के दौरान जमीन पर बैठ गए थे और उनकी एनर्जी देखकर उन्हें दिवंगत अभिनेता देव आनंद की याद आ गई थी। हालांकि, शक्तिमान के किरदार के लिए मुकेश खन्ना को रणवीर की इमेज सही नहीं लगती। उन्होंने कहा, 'रणवीर सिंह 'धुरंधर', 'गली बॉय' और खिलजी का किरदार निभा सकते हैं, लेकिन शक्तिमान नहीं।' मुकेश खन्ना के मुताबिक, शक्तिमान के लिए एक खास तरह की इमेज और चेहरा चाहिए। उनका मानना है कि रणवीर का चेहरा शरारती और चालाक नजर आता है, जबकि शक्तिमान का चेहरा और व्यक्तित्व पूरी तरह सकारात्मक होना चाहिए। रणवीर को इस रोल में देखना चाहते हैं मुकेश दिलचस्प बात यह है कि मुकेश खन्ना रणवीर सिंह को पूरी तरह फिल्म से बाहर नहीं करना चाहते। उन्होंने रणवीर को किलविश का किरदार ऑफर करने की बात भी कही थी। उनका मानना है कि रणवीर ने 'पद्मावत' में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार जिस तरह निभाया था, उसे देखते हुए वह किलविश के रोल में अच्छे लग सकते हैं। बता दें कि किलविश 'शक्तिमान' में विलेन का किरदार है।



वेलवेट का स्टाइलिश फैक्टर



पुरुषों में वेलवेट

70 के दशक में एक्टर इफ्तिखार ने वेलवेट का स्मोकी जैकेट पहना था। उसके बाद कुछ दिनों तक इसका क्रेज रहा, लेकिन धीरे-धीरे वेलवेट के जैकेट का क्रेज कम होता गया। अभी हाल में अभिषेक बच्चन ने भी वेलवेट का जैकेट पहना था, लेकिन ड्रेससेंस से यह मैच नहीं खा रहा था। जबकि ऋतिक रोशन के ऊपर वेलवेट का यह जैकेट खूब फब रहा था। पुरुषों को वेलवेट का जैकेट पहनते समय अपना हेयरस्टाइल और पर्सनाल्टी देखना चाहिए।

कोई भी चीज एकदम में समाप्त नहीं हो जाती, खासकर फैशन में तो बिल्कुल नहीं। यह अलग बात है कि कुछ समय के लिए किसी भी फैशन का ट्रेंड समाप्त हो जाए, लेकिन वह एक बार फिर उसी लुक में या कुछ बदलाव के बाद नए लुक में दोबारा आता है। वेलवेट के साथ भी यही हुआ। 70-80 के दशक में धूम मचाने के बाद यह एक बार फिर से लौटा आया है।

परंपरागत भारतीय ड्रेस

सूट, लहंगा और साड़ी में वेलवेट के इस्तेमाल का चलन इन दिनों काफी बढ़ गया है। चाहे वह एप्लीक वर्क के रूप में हो या फिर बॉर्डर को सजाने में। वेलवेट एक रिच फैब्रिक है और लंबे समय बाद ट्रेंड में है। साड़ी के बॉर्डर से लेकर अनारकली सलवार-कमीज तक यह खूब पसंद किया जा रहा है। वेलवेट के इस ड्रेस को सिलेब्रिटीज भी खूब पसंद कर रहे हैं।

वेलवेट का आधुनिक तड़का

ड्रेस डिजाइनर मानते हैं कि, वेलवेट ट्रिमिंग इन दिनों काफी लोकप्रिय हो रहा है। लोग अब नेट की साड़ी या दुपट्टे पर एक इंच का वेलवेट बॉर्डर चाहते हैं। किसी और समय के मुकाबले इसकी मांग इन दिनों सबसे ज्यादा है। मार्केट में इन दिनों कई तरह के वेलवेट उपलब्ध हैं। जिनमें पॉलिस्टर, विस्कोस और सिल्क हैं। इनमें सिल्क सबसे ज्यादा चमकदार और खर्चीला होता है। वैसे विस्कोस भी सिल्क जैसा ही प्रभाव पैदा करता है, वह भी कम खर्च में। वेलवेट में 'बर्न्ट-आउट वेलवेट भी काफी लोकप्रिय हो रहा है। यह एक सिल्क जॉर्जेट फ्रेबिक है, जिस पर लाइक्रा और वेलवेट की थोड़ी सी इम्बॉसिंग होती है। यदि आपका ड्रेस एक चौड़े बॉर्डर वाला हो तो यह उस पर खूब फबता है। कुछ लोग कुंदन के काम वाले फुल वेलवेट शेरवानी और जैकेट भी पसंद करते हैं।

क्या है खास

साड़ी के पल्लू और ब्लाउज में वेलवेट वर्क काफी पसंद किया जाता है। वैसे, वेलवेट ब्लाउज तभी अच्छा लगता है, जब इसमें कम फैब्रिक यूज हो और इसका डिजाइन, कलर व वर्क साड़ी से ज्यादा हाइलाइट न हो। इन दिनों यह सूट-सलवार में भी खूब यूज हो रहा है। एक प्रभावी चौड़े वेलवेट बॉर्डर वाला सूट या लहंगा लंबे लोगों पर काफी फबता है।

सिलेब्रिटीज को है पसंद

वेलवेट की दीवानगी बहुत ज्यादा नहीं रही है। पिछले दिनों माधुरी दीक्षित, उर्मिला मातोंडकर, रानी मुखर्जी और ऐश्वर्या राय जैसी अभिनेत्रियां वेलवेट से बने परंपरागत ड्रेस में नजर आईं। वेलवेट का इस्तेमाल ज्यादातर परंपरागत ड्रेस लहंगा, सलवार कमीज और साड़ी में होता है। इनमें कशीदकारी बहुत ही बारीक और सुंदर रूप से उभर कर आती है। एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने 90 के दशक में लंबे व स्ट्रेट वेलवेट कुर्ते पहने थे, जिसे लोगों ने ज्यादा नोटिस नहीं किया था। लेकिन कुछ समय तक ब्राइडल आउटफिट्स का पार्ट रहने के बाद यह फैब्रिक मेनस्ट्रीम ड्रेसेज का पार्ट हो गया है। वैसे इस फैब्रिक को बॉलीवुड से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।

ऑफ शोल्डर ड्रेसेज

- ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनने के लिए सबसे जरूरी है कि आप उसे एलिगेंट ज्वैलरी और परफेक्ट मेकअप के साथ कंबाइन करें।
- फैशनेबल लुक के लिए ड्रेस को लंबी इयररिंग्स और पंकी नेकलेस के साथ पहनें।
- मेकअप को कम से कम रखें और बालों को बांध लें, ताकि फोकस आपके शोल्डर्स पर रहे।
- इवनिंग लुक के लिए ड्रेस को ब्रेव और शैनडलेयर्स के साथ कंबाइन करें।
- छोटे कद की स्त्रियों को ऑफ शोल्डर ड्रेसेज पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें उनका कद और छोटा लग सकता है।
- जिनकी बांहें अधिक हेवी हैं, उन्हें भी ऑफ शोल्डर ड्रेसेज नहीं पहनना चाहिए।
- ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपके आर्म्स और अंडर आर्म्स ठीक तरह से वैक्ड और मॉयश्चराइज्ड हैं।
- ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनने से कुछ दिन पहले आर्म्स और शोल्डर्स को टोन करने के लिए वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज भी कर सकती हैं।
- ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनते समय सही सपोर्ट का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए आप सही इनरवेयर का चयन करें।
- ग्लैमर लुक के लिए शोल्डर व नेक पर टैटू का इस्तेमाल भी कर सकती हैं।

एंक्लेट्स का ट्रेंडी फंडा

एक समय पैरो में सजी पायल और उससे निकले वाली मधुर ध्वनि सबको अपनी ओरे आकर्षित करती थी लेकिन अब इसका फैशन पुराना पड़ गया है। आजकल एंक्लेट चलन में है। कॉलेज गोइंग गर्ल्स आज पायल की जगह एंक्लेट पहनना ज्यादा पसंद करती हैं।



लेदर एंक्लेटस

टॉम बाय पर्सनैलिटी की लड़कियों को लेदर का एंकलेट्स बहुत खूबसूरत लगता है। यदि आप लेदर का एंकलेट्स पहन रहीं हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि यह बहुत चौड़ी न हो नहीं तो यह आप के लुक को डाउन कर देगा।

एक पैर में पहना जाने वाला यह एंक्लेट कॉलेज गोइंग गर्ल्स के बीच काफी पसंद किया जा रहा है। स्टाइलिश लुक के लिए कई तरह की एंक्लेट्स मार्केट में है। आप इन्हें अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से चूज कर सकती हैं। आइए जानते हैं तरह-तरह के एंक्लेट्स के बारे में।

ऑरनामेंटल हैं खास

क्रिस्टल के बने एंकलेट्स बहुत ही खूबसूरत होने के साथ स्टाइलिश भी होते हैं। इसे पहनने के बाद आपको किसी तरह की खास एक्सेसरीज की जरूरत नहीं है। सिंपल और सोबर ड्रेस के साथ आप इसे पहन सकती हैं। ब्लैक, वाइट और ग्रे कलर के आउटफिट के साथ ये ज्यादा खूबसूरत लगती हैं।

चेन से सिंपल लुक

सिंपल एंकलेट्स की मार्केट में बहुत सी वैरायटी है। इसमें आप चाहें तो सिंगल लेयर से लेकर चार लेयर तक की एंकलेट्स का यूज कर सकती हैं। एंकलेट्स के साथ ही नेकलेस पहनना बेहतर रहता है। सिंपल एंकलेट्स शॉर्ट स्कर्ट और कैप्री पर पहनने से लुक काफी ग्लैमरस हो जाता है।

बीड्स एंकलेट्स

इस तरेह के एंकलेट्से की खासियत है कि आप इसे किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकती हैं। ये एंकलेट्स आपको सिंपल लुक देती हैं। इन्हें पहनते समय ध्यान रखें कि ज्यादा मेकअप और जूलरी न पहनें। बीड्स का रंग आपकी ड्रेस से मेल खाता हुआ होना चाहिए इससे आपका लुक परफेक्ट लगेगा।

पर्श पर भी नहीं है भारी

इन एंकलेट्स की सबसे खास बात यह है कि इनकी कीमतें सभी लोगों की पहुंच में हैं। यह लोकल मार्केट में ये 20 से लेकर 50 रुपये तक है। वहीं बड़ शोरूमों में इनकी कीमतें 200 से लेकर 500 रुपये तक है।

पैर भी लगें स्टाइलिश

ड्रेस कोई भी हो लेकिन गर्ल्स एंक्लेट पहनना नहीं भूलती। इन दिनों कैप्री के साथ इसका चलन अधिक हो गया है। एंक्लेट पहनने से पैरों की खूबसूरती अधिक बढ़ जाती है। बीबीए स्टूडेंट डिंपल कहती हैं कि एंक्लेट कैप्री या शॉर्ट स्कर्ट के साथ पहना जाए तो डिफरेंट लुक देता है साथ ही साथ पैरों की खूबसूरती भी बढ़ जाती है।

ये हैं फेवरेट स्टाइल

थीन वायर एंक्लेट, छोटी बीड एंक्लेट, मल्टी कलर एंक्लेट,चोटी स्टाइल एंक्लेट, गोल्डेन, सिल्वर चेन एंक्लेट, बंधेज स्टाइल, मैटल स्टाइल, क्रिस्टल स्टाइल, शो-पीस घुंघरू स्टाइल।

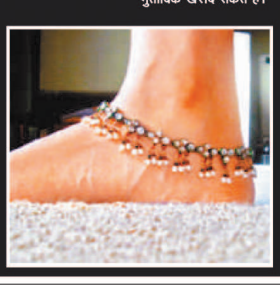
कलरफुल एंक्लेट्स

फिलहाल कॉलेज गोइंग गर्ल्स से लेकर महिलाएं भी मैचिंग तथा कलरफुल एंक्लेट्स पहनने लगी हैं। वैसे कलरफुल एंक्लेट्स को हर ड्रेस पर पहना जा सकता है।

नग वाला एंकलेट्स

नए वाला एंकलेट्स अभी-अभी मार्केट में आया है लेकिन इसकी मांग सबसे अधिक है। नग एंकलेट्स को साड़ी, सूट और अन्य ड्रेस के मैचिंग को ध्यान में रखकर पहना जा सकता है। नग वाली एंकलेट्स मल्टी कलर में भी मिलती है। मल्टी कलर का एंकलेट्स सभी ड्रेसेज पर पर फबता है। और यदि डार्क कलर हो तो कहना ही क्या। हैवी नग वाली एंकलेट्स को शादी, पार्टी जैसे मौकों पर पहन सकती है। इसमें सिंगल से लेकर पांच लेयर तक की एंकलेट्स है जो आप अपनी जरूरत के मुताबिक खरीद सकते है।





सब्जियां जो स्वाद बनाएं बेहतर

आप रोजाना घर में सब्जियां बनाते-बनाते परेशान हो गई हैं, लेकिन घर के सदस्यों को स्वाद बढ़िया नहीं लगता। रोज-रोज की झंझट में क्या बनाएं, क्या न बनाएं, कुछ समझ नहीं आता। आइए, हम सब्जियों की रेसिपी बताते हैं, जिससे आप सब्जियां बनाकर न केवल परिवार का दिल जीत लेंगी, वरना आपको भी इनका स्वाद बढ़िया लगेगा।

पालक पनीर



सामग्री - डेढ़ कप पालक, 500 ग्राम पनीर, एक चम्मच अदरक, एक चम्मच लहसुन, आधा कप प्याज (कसा हुआ), एक कप टमाटर (कटा हुआ), आधा कप प्याज, एक कप टमाटर (बारीक कटा हुआ), एक चम्मच जीरा, चौथाई चम्मच गर्म मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार और एक चौथाई कप तेल।

विधि - तेल गर्म करें और उसमें जीरा मिला दें। जब यह चटकने लगे, तो इसमें अदरक व लहसुन का पेस्ट मिलाएं। इसमें प्याज मिला दें और सभी चीजों को ब्राउन होने दें। इसमें टमाटर मिलाकर मध्यम आंच पर भूनें। अब इसमें गर्म मसाला, नमक और लाल मिर्च पाउडर मिला दें। इसमें पालक को मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद पनीर मिला लें। पांच मिनट तक हल्की आंच पर रहने दें और गर्मागर्म सर्व करें।

पालक-मंगोड़ी



आवश्यक सामग्री - पालक - 750 ग्राम (एक बन्च) चीनी - आधा छोटी चम्मच मूंग दाल की मंगोड़ी - 100 ग्राम (एक कप) टमाटर - 4 (मीडियम आकार के) हरी मिर्च - 1-2 अदरक - 1 इंच लम्बा टुकड़ा तेल - 2 टेबल स्पून हींग - 1 पिंच जीरा - आधा छोटा चम्मच खड़ा मसाला हल्दी पाउडर - एक चौथाई छोटी चम्मच क्रीम या ताजा मलाई - 2 टेबल स्पून(यदि आप चाहें) बेसन - एक टेबल स्पून नमक - स्वादानुसार (1 छोटी चम्मच) लाल मिर्च - 1/4 छोटी चम्मच (यदि आप चाहें) हरा धनियां - 2 टेबल स्पून (बारीक कतरा हुआ)

विधि - पालक के पत्तों से डंडिया हटा कर अलग कर दीजिए। पत्तों के पानी में अच्छी तरह डुबा कर 2 बार धो कर छलनी में या थाली में तिरछा करके रख दीजिए और पालक के पते से पानी निकल जाने दीजिए। पालक के धुले पते को किसी बर्तन में डालिए, आधा कप पानी और चीनी डाल कर, मध्यम आग पर उबालने के लिए ढंककर रख दीजिए। 8-10 मिनट में पालक उबल जाता है। आग बन्द कर दीजिए। कढ़ाई में 1 टेबल स्पून तेल डालकर गरम कीजिए, गरम तेल में, मूंग दाल की मंगोड़ी डाल कर मध्यम आग पर हल्की ब्राउन होने तक भून लीजिए, भुनी मगोड़ी को प्याले में निकाल कर अलग रख लीजिए। अब मसाले में क्रीम डालिए और 2 मिनट और भून लीजिए भुने मसाले में मगोड़ी, डेढ़ कप पानी, भुना हुआ बेसन और नमक डालकर, ढंककर, धीमी आग पर पकने दीजिए। मंगोड़ी नरम हो जाने पर पिसा पालक डालिए। अगर पानी कम लग रहा हो तो आवश्यकतानुसार और पानी मिला दीजिए। सब्जी में उबाल आने के बाद 2-3 मिनट सब्जी को पकने दीजिए। पालक मगोड़ी की सब्जी तैयार है, गैस बन्द कर दीजिए। सब्जी में गरम मसाला और हरा धनियां डाल कर मिला दीजिए। पालक मगोड़ी की सब्जी तैयार है। पालक मगोड़ी की सब्जी को प्याले में निकालिए और ऊपर से थोड़ी सी क्रीम डाल कर सजाइए। गरमा गरम पालक मंगोड़ी की सब्जी चपाती, नान या चावल के साथ परोसिए और खाइए।

धान खरीदी की तैयारियों को लेकर अधिकारियों-कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण

पारदर्शी खरीदी के लिए दिए गए विस्तृत दिशा-निर्देश, दो पालियों में छुईखदान और खैरागढ़ विकासखंड के नोडल अधिकारियों, समिति प्रबंधकों एवं कम्प्यूटर ऑपरेटरों ने लिया प्रशिक्षण

नई दृष्टिबिंदु / खैरागढ़

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों से धान की खरीदी सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं सुगमतापूर्वक सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के मार्गदर्शन में जिला कार्यालय के सभाकक्ष में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के धान उपार्जन केंद्रों के नोडल अधिकारियों, समिति प्रबंधकों एवं कम्प्यूटर ऑपरेटरों को धान खरीदी की प्रक्रिया और शासन के दिशा-निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर सुरेन्द्र कुमार ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अविनाश ठाकुर, खाद्य अधिकारी देवेंद्र कुमार बग्गा सहित संबंधित अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण दो पालियों में संपन्न हुआ। प्रथम पाली में छुईखदान विकासखंड तथा द्वितीय पाली में खैरागढ़ विकासखंड के धान खरीदी केंद्रों से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षकों ने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन धान खरीदी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान किया। अधिकारियों को किसानों की सुविधा, सही तौल, गुणवत्ता परीक्षण और खरीदी संबंधी अभिलेखों के संधारण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

प्रशिक्षण में बताया गया कि उपार्जन अवधि के दौरान किसानों को उनके रकबे के आधार पर टोकन जारी किए जाएंगे। दो एकड़ तक रकबे वाले किसानों को एक, दो एकड़ से अधिक एवं दस एकड़ तक रकबे वाले किसानों को दो तथा दस एकड़ से अधिक रकबे वाले किसानों को अधिकतम तीन टोकन जारी किए जाएंगे। प्रत्येक उपार्जन केंद्र को खरीदी प्रारंभ होने से पहले शासन के प्रतिनिधि जिला विपणन अधिकारी के साथ लिखित अनुबंध करना अनिवार्य होगा।

धान खरीदी के लिए भारत सरकार के एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीकृत किसानों की फार्मर आईडी के माध्यम से पहचान की जाएगी। बायोमेट्रिक डिवाइस से सत्यापन कर निर्धारित रकबे के अनुसार धान खरीदा जाएगा। सामान्य पंजीकृत



किसानों को उपार्जन केंद्र में ऋण पुस्तिका लाना अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि, अधिया एवं रेगहा के माध्यम से धान विक्रय करने वाले किसानों को ऋण पुस्तिका, स्वयं का वचन पत्र तथा भू-स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा।

प्रशिक्षण में स्पष्ट किया गया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे आधारित रकबा ही धान खरीदी के लिए अंतिम रूप से मान्य होगा। संयुक्त खाते के मामले में केवल लंबरदार का एग्रीस्टेक पंजीयन स्वीकार किया जाएगा। बीज निगम में पंजीकृत किसानों की सूची के आधार पर धान की दोहरी बिक्री रोकने के लिए विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। असमानक घोषित धान बीज को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए भी संबंधित किसान का एग्रीस्टेक पंजीयन अनिवार्य होगा।

सभी उपार्जन केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा-बांट का सत्यापन तथा आर्द्रतामापी यंत्र का अंशांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। धान की तौल इलेक्ट्रॉनिक कांटे से की जाएगी। विशेष परिस्थिति में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुमति से ही मैनुअल कांटे का उपयोग किया जा सकेगा। पंजीकृत किसानों से निर्धारित औसत अच्छी किस्म के मापदंडों के अनुरूप धान खरीदा जाएगा। प्रत्येक केंद्र में गुणवत्ता निर्धारण निगरानी समिति धान की गुणवत्ता की निगरानी करेगी। प्रत्येक कट्टे में धान की मात्रा 40 किलोग्राम रखी जाएगी तथा नए बारदाने का निर्धारित वजन 545 से 626 ग्राम तक अलग से लिया जाएगा।

उपार्जित धान में नमी की मात्रा 17 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। धान का भंडारण पक्के चबूतरे अथवा दोहरी परत वाले डनेज के ऊपर करने तथा धान से भरे बोरों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त तिरपाल एवं कैप कवर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वफर लिमिट से अधिक भंडारण की स्थिति में 1,200 क्विंटल अर्थात 3,000 कट्टों के स्टेक बनाए जाएंगे। अलग-अलग किस्म के धान का भंडारण अलग-अलग स्टेक में किया जाएगा। बोरों को गणना योग्य तरीके से रखने तथा प्रत्येक स्टेक में लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई के अनुसार बोरों की संख्या दर्शाने वाला स्टेक प्लान लगाने के निर्देश दिए गए।

आवश्यकतानुसार परिवहन आदेश के माध्यम से धान को संग्रहण केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। परिवहन से पहले समितियों के व्यय पर 10 प्रतिशत धान का रैंडम वजन करने के प्रावधान की भी जानकारी दी गई। धान खरीदी में नए एवं पुराने बारदानों का उपयोग 50:50 के अनुपात में किया जाएगा। नए तथा पुराने बारदानों को अलग-अलग एवं गणना योग्य तरीके से रखना होगा। पुराने बारदानों पर उपयोग से पहले नीले रंग में 'Used bag allowed for KMS 2026-27 का स्टेंसिल लगाना अनिवार्य होगा।

प्रशिक्षण में प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी की सीमा तथा कृषक आदान सहायता संबंधी प्रावधानों की जानकारी भी दी गई। निर्धारित अधिकतम सीमा से कम मात्रा में धान विक्रय करने की स्थिति में बेची गई मात्रा एवं अधिकतम खरीदी योग्य मात्रा के अंतर पर नियमानुसार कृषक आदान सहायता की जानकारी दी गई।

धान खरीदी में पारदर्शिता बनाए रखने एवं अनियमितताओं की रोकथाम के लिए नोडल अधिकारियों को प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को आवंटित उपार्जन केंद्रों का मोबाइल ऐप के माध्यम से भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए। सत्यापन के दौरान ऐप के सभी बिंदुओं की जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करने को कहा गया, ताकि फर्जी खरीदी अथवा उपार्जित धान की मात्रा में कमी जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। यह भी स्पष्ट किया गया कि उपार्जन केंद्रों में भंडारित धान के लिए किसी भी प्रकार की सूखत मात्रा मान्य नहीं होगी।

जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शासन के दिशा-निर्देशों का जिम्मेदारीपूर्वक पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खरीदी केंद्रों में किसानों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने, धान की सही तौल, गुणवत्ता, सुरक्षित भंडारण एवं समय पर परिवहन की व्यवस्था करने पर विशेष जोर दिया गया, ताकि जिले के किसानों को धान विक्रय के दौरान अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

खास खबर

नया धान उपार्जन केन्द्र खुलने से चार गांवों के पंजीकृत किसानों को मिलेगी सुविधा

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव



राज्य शासन द्वारा धान खरीदी व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ बनाने लगातार प्रयास किए जा रहे है। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़े और उन्हें धान विक्रय में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए नए धान उपार्जन केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

शासन की इस पहल से किसानों के समय, श्रम एवं परिवहन खर्च में बचत होगी। इसी कड़ी में राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम मनकी में नवीन धान उपार्जन केन्द्र खुलना किसान महेन्द्र यादव के लिए बड़ी राहत लेकर आयी है। ग्राम मनकी निवासी किसान महेन्द्र यादव ने बताया कि पहले अपनी उपज बेचने के लिए लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित धान उपार्जन केन्द्र सोमनी जाना पड़ता था। इस दौरान टोल प्लाजा भी पार करना पड़ता था। धान को इतनी दूर तक ले जाने में काफी समय और मेहनत लगती थी। परिवहन के दौरान कई बार धान की बोरियां गिर जाने से नुकसान होने की आशंका बनी रहती थी। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान के साथ ही अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि अब गांव के पास ही नया धान उपार्जन केन्द्र खुल जाने से किसानों की परेशानी दूर हो गई है। अब धान बेचने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इससे परिवहन में लगने वाले पेट्रोल-डीजल के खर्च में कमी आएगी और समय एवं मेहनत की भी बचत होगी। गांव के नजदीक धान उपार्जन केन्द्र की सुविधा मिलने से किसानों में खुशी और उत्साह है।

किसान महेन्द्र यादव ने कहा कि शासन द्वारा किसानों की समस्या को देखते हुए ग्राम मनकी में नवीन धान उपार्जन केन्द्र प्रारंभ किया गया है। नवीन धान उपार्जन केन्द्र खुलने से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए सुविधा होगी। साथ ही इससे क्षेत्र के अन्य किसानों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने नवीन धान उपार्जन केन्द्र के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। उल्लेखनीय है कि नवीन धान उपार्जन केन्द्र मनकी में कुल 631 किसान पंजीकृत हैं। इस केन्द्र के प्रारंभ होने से ग्राम सुंदरा, पारी, तोरनकट्टा एवं मनकी के किसानों को धान उपार्जन की सुविधा मिलेगी। अब किसानों को धान विक्रय के लिए दूरस्थ उपार्जन केन्द्रों तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जिससे किसानों के समय एवं परिवहन व्यय की बचत होगी। नवीन धान उपार्जन केन्द्र मनकी में धान खरीदी के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।

कबीरधाम में 18 नवंबर को मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस

कवर्धा। कबीरधाम जिले में 18 नवंबर को जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में किया जाएगा। इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा सहित देश के महान जनजातीय नायकों के अदम्य साहस, संघर्ष, बलिदान और देश की स्वतंत्रता एवं समाज के उत्थान में उनके अतुलनीय योगदान को याद किया जाएगा। कार्यक्रम में सांसद संतोष पाण्डेय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

आयोजन में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, जनजातीय समाज के प्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों की सहभागिता रहेगी। कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के निर्देश पर जिला स्तरीय आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। संबंधित विभागों को कार्यक्रम की सुव्यवस्थित रूपरेखा तैयार करने तथा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आयोजन गरिमामय एवं भव्य तरीके से संपन्न हो सके। जनजातीय गौरव दिवस का उद्देश्य जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों के महत्वपूर्ण योगदान को जन-जन तक पहुंचाना है।

कलेक्टर ने निमार्णाधीन महतारी सदन का किया निरीक्षण, समय सीमा में पूर्ण करने के दिए निर्देश



नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने आज सहसपुर लोहारा विकासखंड के ग्राम चारभाठा में निमार्णाधीन महतारी सदन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों से कार्य की वर्तमान स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश देते हुए कहा कि महतारी सदन का निर्माण निर्धारित समय-सीमा में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। उन्होंने निर्माण में उपयोग की जा रही सामग्री एवं कार्य की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखने तथा निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि महतारी सदन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण सुविधा केंद्र साबित होगा। इसके निर्माण से महिलाओं को विभिन्न गतिविधियों एवं सामुदायिक आयोजनों के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध हो सकेगा। इसलिए संबंधित अधिकारी निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए इसे समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक अग्रवाल, एसडीएम महेश राजपूत, जिला खाद्य अधिकारी चंद्रशेखर देवांगन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने धान खरीदी व संग्रहण केंद्रों का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा

कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने आज सहसपुर लोहारा विकासखंड के विभिन्न धान उपार्जन एवं संग्रहण केंद्रों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राज्य में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर प्रारंभ हो रही धान खरीदी के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने धान उपार्जन केंद्र महराजपुर, बाजार चारभाठा, राजपुर, टाटीकसा एवं धान संग्रहण केंद्र चारभाठा का जायजा लिया। उन्होंने समिति प्रबंधकों एवं संबंधित अधिकारियों से धान खरीदी की तैयारियों, संग्रहण केंद्रों की व्यवस्था तथा अब तक जारी किए गए टोकन की स्थिति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि धान खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए तथा किसानों को उपार्जन केंद्रों में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कलेक्टर ने सभी धान खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए शुद्ध पेयजल, छायादार स्थान, मेडिकल किट, बैठने के लिए कुर्सियों तथा शौचालय सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी शासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। इसलिए सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करें और खरीदी केंद्रों में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक अग्रवाल, एसडीएम महेश राजपूत, जिला खाद्य अधिकारी चंद्रशेखर देवांगन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

कृषक उन्नति योजना से किसानों को मिल रहा आर्थिक संबल, किसान ओमप्रकाश शहारे ने सीएम के प्रति जताया आभार



नई दृष्टिबिंदु / मोहला

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों के हित में लिए जा रहे निर्णयों और संचालित की जा रही किसान हितैषी योजनाओं से किसानों को आर्थिक संबल मिल रहा है। शासन द्वारा धान खरीदी की बेहतर व्यवस्था और किसानों की सुविधा के लिए किए जा रहे प्रयासों से किसानों में उत्साह का माहौल है। इसी कड़ी में मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के ग्राम बंजारी निवासी किसान ओमप्रकाश शहारे ने कृषक उन्नति योजना से मिलने वाले लाभ और धान खरीदी की सुविधाओं पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया है।

किसान ओमप्रकाश शहारे ने बताया कि कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा उन्हें कृषक उन्नति योजना के प्रावधानों एवं लाभों की जानकारी दी गई है। योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान के मान से लाभ दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि योजना के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वास्तविक धान उत्पादन कम होने की स्थिति में भी पात्र किसानों को निर्धारित मापदंडों के अनुरूप लाभ मिल सकेगा। उन्हें इस संबंध में प्रति एकड़ 13,849 रुपये की राशि मिलने की जानकारी दी गई है। इससे कम उत्पादन वाले किसानों को भी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

उन्होंने बताया कि धान खरीदी प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए शासन द्वारा तुहर टोकन ऐप की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस ऐप के माध्यम से किसान घर बैठे ही अपने धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त कर सकते हैं। इससे टोकन कटवाने के लिए बार-बार धान खरीदी केंद्रों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही किसानों के समय और श्रम की बचत होगी तथा धान विक्रय की प्रक्रिया भी अधिक सुविधाजनक बनेगी।

श्री शहारे ने कहा कि शासन की किसान हितैषी योजनाओं और सुविधाओं से किसानों को लगातार राहत मिल रही है। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता तथा तुहर टोकन ऐप जैसी डिजिटल सुविधाएं किसानों के लिए काफी उपयोगी साबित हो रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने, उनकी मेहनत का सम्मान करने और कृषि कार्य को सुविधाजनक बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है।

अवैध धान परिवहन व बिक्री पर निगरानी के लिए जांच समितियां गठित, जिले में 13 चेक पोस्ट स्थापित

नई दृष्टिबिंदु / खैरागढ़

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान उपार्जन की निगरानी तथा अवैध धान परिवहन एवं बिक्री पर नियंत्रण के लिए खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में जिला एवं तहसील स्तरीय जांच समितियों का गठन किया गया है। अन्य राज्यों से अवैध रूप से आने वाले धान पर नियंत्रण के लिए गातापार जंगल और रेंगाखार में दो अंतरराज्यीय चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। इन चेक पोस्ट पर मंडी, राजस्व, वन एवं पुलिस विभाग के कर्मचारी 24 घंटे तैनात रहकर निगरानी करेंगे। इसी प्रकार जिले में 11 अंतरजिला चेक पोस्ट भी स्थापित किए गए हैं।

छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशों के परिपालन में अपर कलेक्टर सुरेन्द्र कुमार ठाकुर ने जांच समितियों के गठन संबंधी आदेश जारी किए हैं। समितियां धान खरीदी की निगरानी करने के साथ जिले को प्राप्त अलर्ट के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगी। चेक पोस्ट एवं विभागीय जांच टीमों के माध्यम से अवैध धान की आवक, परिवहन और बिक्री पर नजर रखी जाएगी।

जिला स्तरीय जांच समिति में अपर कलेक्टर सुरेन्द्र कुमार ठाकुर, खाद्य अधिकारी देवेन्द्र बग्गा, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं आर.के. झा, जिला विपणन अधिकारी चंद्रपाल दीवान, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम श्रीमती शबाना परवीन खान, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव के खैरागढ़ परिक्षेत्र के नोडल अधिकारी योगेन्द्र शर्मा, मंडी सचिव खैरागढ़ सुदेश बघेल तथा मंडी सचिव गंडई दीनदयाल सोनवानी को शामिल किया गया है।

जिला स्तरीय जांच समिति के अधिकारियों के संपर्क नंबर

सुरेन्द्र कुमार ठाकुर, अपर कलेक्टर — 9425262593, देवेन्द्र बग्गा, खाद्य अधिकारी — 8109142111, आर.के. झा, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं — 7999898317, चंद्रपाल दीवान, जिला विपणन अधिकारी — 9303812576, श्रीमती शबाना परवीन खान, जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम — 8109466370, योगेन्द्र शर्मा, नोडल अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, परिक्षेत्र खैरागढ़ — 9424105875, सुदेश बघेल, मंडी सचिव, खैरागढ़ — 7898731574, दीनदयाल सोनवानी, मंडी सचिव, गंडई — 9752013550

तहसील स्तर पर खैरागढ़, गंडई, छुईखदान और साल्हेवारा के लिए जांच टीमें गठित की गई हैं। आदेश में इन टीमों के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री अविनाश ठाकुर को अनुभाग का नोडल अधिकारी बनाया गया है। टीमों में राजस्व, खाद्य, सहकारिता, मंडी एवं वन विभाग के अधिकारियों को शामिल कर संयुक्त निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है।

खैरागढ़ तहसील की टीम में राजस्व विभाग से भूपेन्द्र कुमार नेताम, देवेश प्रसाद साहू एवं श्रीमती नेहा ध्रुव, खाद्य विभाग से खाद्य निरीक्षक विनोद कुमार सागर एवं मनीष कुमार ध्रुव, सहकारिता विभाग से सहकारिता निरीक्षक प्रदीप कुमार मालेकर, मंडी विभाग से उप निरीक्षक हरीश सिंह तथा वन विभाग से अजय कुमार राजपूत को शामिल किया गया है। गंडई तहसील की टीम में तहसीलदार हुलेश्वर कुमार, छुईखदान की टीम में तहसीलदार आशीष देवहारी तथा साल्हेवारा की टीम में तहसीलदार मोहन लाल झारिया को शामिल किया गया है। इन तीनों तहसीलों की टीमों में खाद्य निरीक्षक सुश्री डालेश्वरी देवहारे, सहकारिता निरीक्षक राजकुमार महिलारे, मंडी निरीक्षक टीआर साहू तथा वन विभाग से गुलशन कुमार साहू को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जारी आदेशों में समितियों में शामिल नोडल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निगरानी संबंधी मोबाइल ऐप इंस्टॉल कराने तथा आवश्यक आईडी एवं पासवर्ड तैयार कराने के निर्देश दिए गए हैं। धान खरीदी अवधि में अवैध धान परिवहन एवं बिक्री की निगरानी और की गई कार्रवाई की जानकारी मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भेजी जाएगी। समिति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पंजीयन की स्वीकृति के लिए जिला खाद्य अधिकारी को सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है।

कार्यक्रम स्वर्ण पदक विजेता तोमन कुमार को 51 लाख और कांस्य पदक विजेता अभिजीत सखूजा को 31 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एशियन पैरा गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित

नई दृष्टिबिंदु / बालोद

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में एशियन पैरा गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन कर देश और छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाने वाले प्रदेश के दो प्रतिभाशाली पैरा खिलाड़ियों तोमन कुमार और अभिजीत सखूजा को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए पैरा तीरंदाजी में स्वर्ण पदक विजेता तोमन कुमार को 51 लाख रुपए और पैरा बैडमिंटन में कांस्य पदक विजेता अभिजीत सखूजा को 31 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को शाल एवं बस्तर कला का प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जीवन में चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हों, यदि मन में



दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो सफलता का कोई भी शिखर असंभव नहीं है। तोमन कुमार और अभिजीत सखूजा ने अपने साहस, कठिन परिश्रम और असाधारण खेल प्रतिभा से इसे सिद्ध कर दिखाया है। दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धियां केवल पदक जीतने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि संघर्ष से सफलता तक की ऐसी प्रेरक गाथाएं हैं, जो प्रदेश के हजारों युवाओं को अपने सपनों को साकार करने का हौसला देंगी।

नक्सली हमले में गंवाया पैर, लेकिन नहीं टूटा हौसला : बालोद जिले के ग्राम नवागांव निवासी श्री तोमन कुमार की सफलता की कहानी अदम्य साहस और दृढ़ इच्छाशक्ति का उदाहरण है। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन में सेवा के दौरान वर्ष 2022 में झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के समय हुए आईईडी विस्फोट में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना में उन्हें अपना बायां पैर गंवाना पड़ा। जीवन की इस कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने हार नहीं मानी। वर्ष 2023 में पैरा तीरंदाजी की शुरूआत की और निरंतर अभ्यास, अनुशासन तथा आत्मविश्वास के बल पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया। मुख्यमंत्री श्री साय ने तोमन कुमार के साहस को नमन करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले इस वीर जवान ने खेल के मैदान में भी अपनी अदम्य इच्छाशक्ति का परिचय दिया है। नक्सलियों के विस्फोट ने उनका एक पैर जरूर छीन लिया, लेकिन देश के लिए कुछ कर दिखाने का उनका जज्बा नहीं छीन सका। पहले मातृभूमि की रक्षा और अब अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर तिरंगे का मान बढ़ाकर उन्होंने छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है।

शारीरिक चुनौती को पीछे छोड़ अभिजीत ने हासिल की अंतरराष्ट्रीय सफलता : बिलासपुर निवासी अभिजीत सखूजा ने भी अपनी मेहनत और लगन से सफलता की प्रेरक मिसाल प्रस्तुत की है। बचपन से क्लब फुट की शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे श्री सखूजा ने परिस्थितियों को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने पैरा बैडमिंटन को अपना लक्ष्य बनाया और कठिन अभ्यास तथा अनुशासन के बल पर अपनी खेल प्रतिभा को निखारा। एशियन पैरा गेम्स में कांस्य पदक जीतकर उन्होंने साबित किया कि मजबूत इरादों और निरंतर प्रयास से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अभिजीत सखूजा की उपलब्धि उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन में आगे बढ़ने का सपना देखते हैं। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों के परिवारजनों को भी बधाई देते हुए कहा कि खिलाड़ियों की सफलता के पीछे परिवार का त्याग, विश्वास और प्रोत्साहन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार : मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता उन्हें उचित अवसर, बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराने की है। राज्य सरकार इसी दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। विशेष रूप से पैरा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ियों को भविष्य की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए राज्य सरकार हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियों को आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग की योजनाओं के अंतर्गत 3 लाख रुपए तक की टीए-डीए सहायता भी प्रदान की जाती है।

इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार, संचालक खेल सुश्री आकांक्षा शिक्षा खलखो सहित दोनों खिलाड़ियों के परिवारजन उपस्थित थे।

जिले में आज से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने नोडल अधिकारियों व समिति प्रबंधकों की ली बैठक, पारदर्शी और सुव्यवस्थित खरीदी के दिए निर्देश

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग



जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का शुभारंभ 15 नवंबर से होने जा रहा है। आगामी धान उपार्जन की तैयारियों को लेकर कलेक्टर अभिजीत सिंह ने साइंस कॉलेज में नोडल अधिकारियों एवं समिति प्रबंधकों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने धान खरीदी प्रक्रिया को त्रुटिरहित, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिले में कुल 123 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 21 नवीन उपार्जन केंद्र शामिल हैं। जिले में धान खरीदी 15 नवंबर से प्रारंभ होकर 15 जनवरी तक चलेगी। गिरदावरी एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य भी पूरा किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि किसानों के हित में शासन द्वारा इस वर्ष महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव किया गया है। इसके तहत यदि कोई किसान अपने कुल दर्ज रकबे के अनुपात में कम धान लेकर भी उपार्जन केंद्र पहुंचता है, तब भी उसे पूरे रकबे के आधार पर आदान सहायता की राशि प्रदान की जाएगी।

धान खरीदी के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत एवं फार्मर आईडी प्राप्त किसानों से निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप धान का उपार्जन किया जाएगा। धान में अधिकतम 17 प्रतिशत तक नमी स्वीकार्य होगी। खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली अपनाई जाएगी। इसके लिए मार्कफेड द्वारा फिंगरप्रिंट एवं आइरिस डिवाइस उपलब्ध कराई गई है। किसान 15 जनवरी तक की अवधि के लिए टोकन प्राप्त कर सकेंगे।

टोकन और पंजीयन की होगी पारदर्शी व्यवस्था

टोकन व्यवस्था के संबंध में बताया गया कि किसानों को 70 प्रतिशत टोकन ऑनलाइन ऐप के माध्यम से तथा शेष 30 प्रतिशत टोकन समितियों के माध्यम से जारी किए जाएंगे। इससे उन किसानों को भी सुविधा मिलेगी, जिनके पास स्मार्टफोन अथवा अन्य डिजिटल साधन उपलब्ध नहीं हैं। वे संबंधित समिति में पहुंचकर आसानी से टोकन प्राप्त कर सकेंगे। निर्धारित भूमि रकबे के आधार पर टोकन की पात्रता तय की गई है। इसके अनुसार 2 एकड़ से कम रकबे वाले किसानों को एक टोकन, 2 से 10 एकड़ तक के किसानों को दो टोकन तथा 10 एकड़ से अधिक रकबे वाले किसानों को तीन टोकन दिए जाएंगे।

बारदाना प्रबंधन एवं स्टॉक की नियमित होगी निगरानी

धान खरीदी के दौरान बारदानों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि इस वर्ष 50 प्रतिशत नए और 50 प्रतिशत पुराने बारदानों का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने सभी उपार्जन केंद्रों में नए एवं पुराने बारदानों का स्टॉक बनाए रखने को कहा। साथ ही बारदानों की कमी की स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए नियमित रूप से स्टॉक की निगरानी करने तथा आवश्यकता के अनुसार तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

धान के स्टैक अलग-अलग बनाने के निर्देश

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने उपार्जन केंद्रों में धान की बोरियों का व्यवस्थित तरीके से स्टैक लगाने के निर्देश दिए, ताकि भौतिक सत्यापन के दौरान बोरियों की गिनती में आसानी हो। उन्होंने मोटा, पतला, सरना एवं अन्य किस्मों के धान के लिए अलग-अलग स्टैक तैयार करने को कहा। इसके अलावा खरीदी केंद्रों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नोडल अधिकारियों को पीवी ऐप एवं खरीदी केंद्र स्मार्ट मूल्यांकन पोर्टल (पीसीएसएपी) में आवश्यक प्रविष्टियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को अपने आवंटित केंद्रों का निरीक्षण कर पीवी ऐप में निरीक्षण प्रतिवेदन अपडेट करने को भी कहा।

धान खरीदी अवधि में मिलर्स को नहीं मिलेगी उठाव की अनुमति

धान खरीदी की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से इस वर्ष महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है। इसके तहत धान खरीदी की पूरी अवधि यानी 15 नवंबर से 15 जनवरी तक किसी भी मिलर को धान उठाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। पिछले वर्षों में धान खरीदी के साथ-साथ मिलर्स द्वारा उठाव किए जाने से रीसाइक्लिंग एवं अनियमितताओं की आशंका बनी रहती थी। इस बार पहले शत-प्रतिशत धान की खरीदी एवं उसका सुरक्षित संग्रहण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।

बैठक में कलेक्टर ने सभी नोडल अधिकारियों एवं समिति प्रबंधकों को निर्देशित किया कि वे आज ही अपने-अपने आवंटित उपार्जन केंद्रों का भौतिक निरीक्षण कर वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लें। उन्होंने पेयजल, शौचालय, फेंसिंग, तौल कांटे सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की जांच कर कमियों को समय रहते दूर करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को धान विक्रय के दौरान बेहतर सुविधाएं मिल सकें और खरीदी का कार्य सुगमता एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न हो। बैठक में अपर कलेक्टर खेमलाल वर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती सृष्टि चंद्राकर, खाद्य अधिकारी अनुराग भदौरिया, जिला विपणन अधिकारी मार्कफेड राहुल कुमार, जिला सहकारी बैंक के ब्रदेश शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना ही होगा एफआईआर और तत्काल गिरफ्तारी भी होना चाहिए : राकेश



नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार संचालित वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान के तहत जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग (ग्रामीण) द्वारा जिलेभर में मंडल एवं ब्लॉक स्तर पर जनचौपाल तथा जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज जिले के तीन अलग-अलग स्थानों पर आयोजित जनचौपाल कार्यक्रमों में जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग (ग्रामीण) के अध्यक्ष राकेश ठाकुर विशेष रूप से शामिल हुए और आम नागरिकों से सीधे संवाद किया।

इस क्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जामूल के तत्वावधान में मंडल कांग्रेस कमेटी शिवपुरी महामाया, जामूल अंतर्गत कन्हार पारा वार्ड क्रमांक 7 में जनचौपाल आयोजित की गई। वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अहिवारा नगर के अंतर्गत बानबरद में तथा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अहिवारा ग्रामीण के कोड़िया मंडल में भी जनचौपाल एवं जनसंवाद कार्यक्रम संपन्न हुए। तीनों स्थानों पर कांग्रेस पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति में लोकतंत्र, संविधान और मताधिकार की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता का वोट है। प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने और उसकी निष्पक्षता पर भरोसा रखने का अधिकार है। लेकिन आज देश में मतदाता सूची की पारदर्शिता, मतदाताओं के नाम काटे जाने तथा निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में इन मुद्दों पर जनता को जागरूक करना और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज बुलंद करना समय की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, जिसकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर देश के लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। चुनाव कराने वाली संस्था का किसी भी राजनीतिक दल के प्रभाव से मुक्त रहना आवश्यक है। मतदाता सूची में पारदर्शिता, चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और निर्वाचन आयोग की जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए और ज्ञानेश कुमार पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही किया जाना चाहिए।

जिलाध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 11 से 15 नवंबर 2026 तक दुर्ग (ग्रामीण) जिले के सभी 39 मंडल कांग्रेस कमेटियों के अंतर्गत जनचौपाल एवं जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 16 से 25 नवम्बर तक उक्त जनचौपाल का आयोजन बूथ स्तर तक किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं एवं समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया जा रहा है। मंडल स्तर पर कार्यक्रमों के संपन्न होने के बाद अभियान को बूथ स्तर तक विस्तारित किया जाएगा, ताकि प्रत्येक मतदाता तक पहुंचकर लोकतांत्रिक अधिकारों और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विषयों पर जागरूकता लाई जा सके।

इस दौरान महापौर निर्मल कोसरे, जयश्री वर्मा, लोचन यादव, कमलेश साहू, करीम खान, प्रकाश ठाकुर, उमेश साहू, संतोष बाफना, सुनीता चन्नेवार, सरोजनी चंदाकर, रामप्यारी वर्मा, सुमन वर्मा, सबीहा खान, दीपती साहू, संजय देशलहरे, ओमकार निर्मलकर, लेखराम साहू, अश्वनी साहू, दीपक साहू, गीतेश्री, गौतम ठाकुर, राजेश साहू, दिनेश निर्मलकर, दीपक धील्लहरे, रीतु ठाकुर, चन्द्रशेखर शर्मा, राधे चौधरी, लेखु साहू, शंकर सेन, सन्त राम, राहुल साहू, रोहित, प्रमिला साहू, दिप्पी देवांगन सहित बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे।

एसबीआई से 1 करोड़ दुर्घटना बीमा का लाभ मिले, कर्मचारी संघ ने एसबीआई को लिखा पत्र

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग



छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला दुर्ग ने शासकीय कर्मचारियों को SBI के State Government Salary Package (SGSP) के तहत मिलने वाले 1 करोड़ रुपये के दुर्घटना बीमा का वास्तविक लाभ दिलाने की मांग उठाई है।

जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने रइक के मुख्य महाप्रबंधक छत्तीसगढ़ सर्किल रायपुर को पत्र भेजकर Diamond श्रेणी के बीमा की पात्रता, शर्तें और क्लेम प्रक्रिया सार्वजनिक करने की मांग की है। संघ ने कहा कि शासन और SBI के बीच 22 दिसंबर 2025 को हुए MoU और वित्त विभाग के 1 जनवरी 2026 के आदेश के तहत कर्मचारियों को यह सुविधा दी गई है। लेकिन क्या खाता Diamond में बदलते ही बीमा स्वतः लागू होता है या अलग पंजीयन जरूरी है, यह स्पष्ट नहीं है। वेतन जमा होने में देरी पर बीमा पर असर पड़ेगा या नहीं, इसे भी स्पष्ट किया जाए। संघ ने मांग की है कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को नाम, पॉलिसी नंबर, बीमा राशि और नॉमिनी विवरण वाला व्यक्तिगत बीमा प्रमाण-पत्र दिया जाए। क्लेम के लिए आवश्यक दस्तावेज, समय-सीमा और अपील प्रक्रिया भी सार्वजनिक हो। साथ ही पेंशनरों के लिए भी रक्षद्ध के तहत समान बीमा सुरक्षा पैकेज बनाया जाए।

मालवीय नगर चौक से जेल तिराहा तक फोरलेन निर्माण को मिली स्वीकृति

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग



छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग ने जिला दुर्ग में मालवीय नगर चौक से जेल तिराहा तक 1.4 किमी मार्ग के फोरलेन निर्माण कार्य के लिए प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री अरुण साव के द्वारा जारी इस स्वीकृति के तहत ?10.01 करोड़ की राशि व्यय की जाएगी। यह स्वीकृति शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की दुर्ग शहर की महत्वपूर्ण योजनाओ मे शामिल है

इधर जेल तिराहा से मिनी माता चौक तक के मार्ग को भी फोरलेन बनाने का कार्य पहले से प्रगति पर है। अब मालवीय नगर चौक से जेल तिराहा तक का स्वीकृत फोरलेन मार्ग इस निमार्णाधीन मार्ग से जुड़ जाएगा। दोनों हिस्से जुड़ने पर एक सतत फोरलेन मार्ग उपलब्ध होगा। इसका लाभ यह होगा कि राजनांदगांव या बालोद की ओर जाने वाले वाहन दुर्ग शहर में प्रवेश किए बिना बाहर से ही निकल सकेंगे। इससे शहर के भीतर यातायात का बड़ा दबाव घटने और लोगों को जाम से राहत मिलेगी ।

मालवीय नगर चौक से जेल तिराहा मार्ग के आसपास कई स्कूल, कॉलेज,लोक निर्माण विभाग के कार्यालय, केंद्रीय जेल, शासकीय आवास, आरटीओ कार्यालय, वन विभाग कार्यालय, इत्यादि स्थित हैं। इस कारण यहां यातायात का दबाव काफी अधिक रहता है। चौड़ीकरण के बाद स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों सहित आम नागरिकों को सुविधा मिलने और दुर्घटनाओं में कमी होगी ।

निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम : दावा-आपत्तियों का निराकरण 19 नवम्बर तक

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिकाओं के आम/ उप निर्वाचन दिसम्बर 2026 सम्पन्न कराए जाने हेतु निर्वाचक नामावली तैयार / पुनरीक्षण करने का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है । जिसके अनुसार 19 नवंबर 2026 तक दावा/ आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। इस तिथि तक जिन मतदाताओं ने विधानसभा की निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करवा लिया है, वे प्रारूप क-1 में नियमानुसार आवेदन करने की पात्रता रखते है। प्रारूप क-1 में 20 नवंबर तक आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे।

कृषक उन्नति योजना पर प्रति एकड़ 13,839 सहायता : भाजपा किसान मोर्चा ने जताया आभार

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर



छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों के हित में कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 13,839 की आदान सहायता देने के निर्णय का भाजपा किसान मोर्चा ने स्वागत किया है। मोर्चा के प्रदेश संयोजक अतुल पर्वत ने इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, कृषि मंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आलोक ठाकुर के प्रति आभार जताया।

अतुल पर्वत ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश के लाखों किसानों के लिए आर्थिक संबल प्रदान करने वाला है। खरीफ वर्ष 2026 से लागू होने वाली इस योजना के तहत सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी।

उन्होंने कहा कि इस सहायता से खेती की लागत कम होगी और किसान आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज, कृषि उपकरणों में निवेश कर सकेंगे। फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी।

पर्वत ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार किसानों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। यह योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के साथ उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार का मार्ग प्रशस्त करेगी। उन्होंने कहा कि घोषणा के बाद प्रदेश के किसानों में उत्साह का माहौल है और यह योजना कृषि व्यवस्था को अधिक मजबूत और आधुनिक बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।

रायपुर में धान खरीदी शुरू! जोरा उपार्जन केंद्र में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने किया शुभारंभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए आज से धान खरीदी का महापर्व शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप रायपुर जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरूआत हो गई है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने जोरा स्थित धान उपार्जन केंद्र पहुंचकर विधिवत पूजा-अर्चना की और धान खरीदी का शुभारंभ किया। खरीदी शुरू होने से किसानों में उत्साह का माहौल है। वहीं, उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।

रायपुर जिले में धान खरीदी की शुरूआत के अवसर पर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह जोरा स्थित धान उपार्जन केंद्र पहुंचे। यहां उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप 15 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी किसानों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। जिले में धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाएगा। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरूआत होने से किसानों में उत्साह देखने को मिल रहा है। अपनी मेहनत से तैयार की गई धान की उपज को बेचने के लिए किसानों का इंतजार अब समाप्त हो गया है। धान खरीदी का शुभारंभ होने के साथ ही रायपुर जिले के किसानों को उपार्जन केंद्रों में अपनी उपज बेचने की सुविधा मिलेगी। खरीदी प्रक्रिया के दौरान किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उपार्जन केंद्रों में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। धान खरीदी के दौरान किसानों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उपार्जन केंद्रों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। खरीदी की शुरूआत के साथ किसानों की सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

Name Change

This is to inform the general public that I, Mahendra Singh Thakur, residing at Quarter No. 15/A, Street 23, Sector 2, Bhilai, have changed my name. Previously, I was known as Mahendra Thakur; I have now changed my name to Mahendra Singh Thakur. Therefore, in all official, semi-official, and other documents, I should henceforth be known and identified as Mahendra Singh Thakur.

Mahendra Singh Thakur
Quarter No. 15/A, Street 23, Sector 2, Bhilai







"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के तहत संपादक जिम्मेदार है)। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।" संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100